CNews सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-226
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

सुविचार

'कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी।'

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

सिटी चीफ

इंदौर, गुरुवार 21 नवम्बर 2024

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

गौतम अडाणी पर अमेरिका में केस

250 मिलियन डॉलर रिश्वत ऑफर करने का आरोप, धोखाधड़ी में शामिल होने का दावा

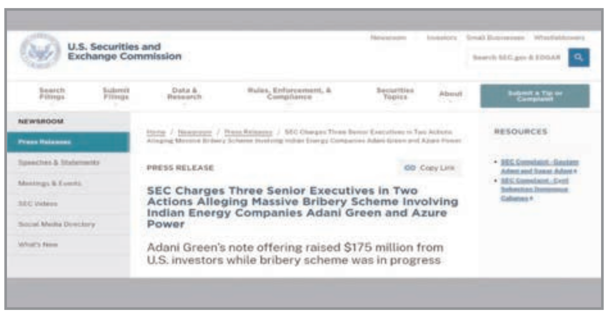

अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी एक नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने बुधवार(20 नवंबर) को गौतम अडाणी और उनके भतीजे सागर समेत 6 लोगों पर रिश्वत ऑफर करने और धोखाधड़ी चार्ज फ्रेम किया। मामला अडाणी ग्रुप के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़ा है। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने दावा किया है कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए अडाणी ग्रुप ने 250 मिलियन डॉलर (करीब 2110 करोड़ रुपए) की रिश्वत ऑफर की। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि गौतम अडाणी, उनके भतीजे सागर अडाणी और अडाणी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले सात लोगों ने भारत की सबसे बड़ी सोलर प्लांट डेवलप करने के लिए भारत के सरकारी अफसरों को 250 मिलियन डॉलर रिश्वत देने की हामी भरी थी। इस प्रोजेक्ट से अडाणी ग्रुप को 20 साल में करीब 2 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होने वाला था। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। यह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद बन गया है।

यूएएस एसईसी ने अडाणी ग्रुप के आरोपों की जानकारी दी एसईसी ने एक बयान में कहा कि कथित साजिश के दौरान, अडाणी ग्रीन ने अमेरिकी निवेशकों से 175 मिलियन अमरीकी डालर से ज्यादा की रकम जुटाई। एज्योर पावर के शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किए गए। इस कंपनी के शेयरों की खरीद-बिक्री की गई। इसके साथ ही, न्यूयॉर्क के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी आफिस ने गौतम अडाणी, सागर अडाणी, कैबनेस और अडानी ग्रीन और एज्योर पावर से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोपों से जुड़ी फाइलें खोल दी है। इस मामले में जिन 6 दूसरे लोगों का नाम शामिल है उनमें रूपेश अग्रवाल, विनीत एस जैन, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रंजीत गुप्त और साइरिल कैबेनिस शामिल है। इनमें से सागर और विनीत एस जैन अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में ऊंचे पदों पर हैं। कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि गौतम अडाणी और उनके भतीजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है।

क्या है अमेरिका में मामला दर्ज होने की वजह? दरअसल, अडाणी के सोलर एनर्जी प्रोजेट में अमेरिकी निवेशकों का पैसा लगा है। अमेरिका के कानून के मुताबिक किसी भी अमेरिकी नागरिक के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत की लेन-देन के लिए नहीं किया जा सकता। यह अमेरिकी कानूनी के मुताबिक, एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अडाणी पर आरोप है कि उन्होंने विदेशी निवेशकों, बैंकों और अमेरिका के नागरिकों से झूठ बोलकर रिश्वत की रकम जुटाई। यही वजह है कि गौतम अडाणी और अडाणी समूह से जुड़े उच्च पदस्थ लोग अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के जांच के दायरे में आ गए। अडाणी ग्रीन ने इन आरोपों की पुष्टि की है। अडाणी ग्रीन ने बुधवार को कहा कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड मेम्बर गौतम अडाणी और सागर अडाणी के खिलाफ न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में क्रिमिनल केस और सिविल कंप्लेन दर्ज कराई है। इसके अलावा, बोर्ड के एक और सदस्य विनीत जैन को भी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आपराधिक मामले में शामिल किया है। इन घटनाओं को देखते हुए, हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल डॉलर वैल्यू वाले बॉन्ड जारी करने की योजना को टालने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, बोले- सामने आया गोधरा कांड का सच

अशोका ओपन थिएटर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखा। जिसकी सभी ने बहुत ही सहराना की। इस दौरान अभिनेता विक्रांत मैसी और अभिनेत्री राशि खन्ना ने भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ फिल्म को देखा। उससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ भेंट भी की और उत्कृष्ट फिल्म में अभिनय के लिए बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गोधरा कांड के सच को दबा कर हमारे बीच गलत तरीके से पेश किया गया था, जिसके बारे में सब जानते है। इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का कारण यह है कि ताकि लोगों के बीच में सही घटना सामने आ पाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने फिल्म को टैक्स फ्री करने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव को दी बधाई। इस मौके पर हरिभूमि ने भाजपा पदाधिकारियों से फिल्म के रिव्यू जाने।

22 साल पहले जो बिता वो जनता के सामने आए- अभिनेता विक्रांत मैसी ने जय महाकाल बोलकर अपनी बात को शुरू किया। विक्रांत ने कहा कि ये फिल्म इसलिए बनाई की जो 22 साल पहले बिता वो जनता के सामने आए, फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का धन्यवाद। मेरी मुंबई के बार सबसे ज्यादा फिल्म मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने से अन्य राज्यों को भी मिलेगी प्रेरणा अभिनेत्री राशि खन्ना बोली महाकाल के दर्शन किए है। ये भोपाल में स्वच्छता देख अच्छा लगा। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होने की ओर राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि यह फिल्म हकीकत से लोगों को वाकिफ कराती है, जो हकीकत हमसे छुप रही थी, उस हकीकत को इस फिल्म ने सबके सामने लाकर एक अच्छा काम किया है। भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि हमारे देश के इतिहास बहुत बड़ा है और यहां इस तरह के कई कांड हुए। जिन पर इस तरह की फिल्म बनना बहुत जरूरी है, ताकि देश के युवा इस तरह की घटना से रूबरू हो सकें। तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किए गए सच को फिल्म के जरिए सामने लाया गया भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि फिल्म देखने के बात हम उस हकीकत को जान पाए है, जिसको तोड़ मरोड़कर लोगों के सामने प्रस्तुति किया गया था। फिल्म के माध्यम से सच्ची घटना तक पहुंचने का बहुत अच्छा प्रयास है। सालों पुराने सच को फिल्म के माध्यम से किया गया है पेश भाजपा प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि जिस सच को कई सालों से लोगों के बीच में गलत तरीके से पेश किया गया था। उसको बहुत बारीक और सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इस तरह की फिल्में बन बहुत जरूरी।

लापता हुईं विनेश फोगाटः वायरल पोस्टर में किया जा रहा दावा, जानें क्या है पूरा मामला

हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी विनेश फोगाट के गुमशुदगी के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि मैडल पहलवान लापता हैं, अगर किसी को दिखें तो जुलाना वालों को सूचित करें। हालांकि, ये पोस्टर किसने लगवाए। इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है। दरअसल, जो पोस्टर वायरल हो रहा है। उसमें विनेश फोगाट की फोटो लगाई गई है। उसके टाइटल में लिखा है कि लापता विधायक की तलाश। नाम-विनेश फोगाट, पेशा- मैडल पहलवान एंव जुलाना हलके से कांग्रेसी विधायक हैं। पूरा विधानसभा सत्र निकल गया। लेकिन, विधायक मैडम पूरे सत्र से लापता है। अगर किसी को दिखें तो जुलाना वालों को सूचित करें। हालांकि, इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस और विनेश फोगाट की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन, ये काफी वायरल हो रहा है। **इस वजह से नहीं पहुंच पाईं विधानसभा सत्र में**- वहीं इस पूरे मामले में विनेश फोगाट के पीए सोनू का कहना है कि विधायक को कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया हुआ है और वह महाराष्ट्र और झारखंड में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर काफी व्यस्त थीं। इसी वजह से विनेश फोगाट विधानसभा सत्र में नहीं पहुंच पाई। लेकिन, उनके हरियाणा में वापस आने पर जुलाना की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। वह कहीं गायब नहीं हुई हैं। बता दें कि हरियाणा में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ है। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जींद की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दी थी। विनेश बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश बैरागी को छह हजार से ज्यादा वोट से हराकर पहली बार विधायक बनी हैं। उन्होंने पैरिस ओलंपिक से आने के बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। यह विनेश के लिए पहला मौका है, जब वह विधानसभा पहुंची हैं।

विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले सर्वे- महाराष्ट्र-झारखंड में एक-एक एग्जिट पोल में 'इंडिया' की सरकार, बाकी सब एजेंसियां जिता रही 'एनडीए' को

...तो आखिरकार चल ही गया 'बंटेंगे तो कटेंगे' का जादू!

महाराष्ट्र-झारखंड में एक-एक एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। बाकी सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया गया है। एक्सिस माय इंडिया के सर्वे में झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। यहां इंडिया गठबंधन को 53, बीजेपी गठबंधन को 25 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं, महाराष्ट्र में इलेक्टोरल एज के सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 118, कांग्रेस गठबंधन को 150 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि अन्य के खाते में 20 सीटें जाती दिख रही हैं।

नई दिल्ली। दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हो गई। इसके बाद एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इस बाद दो दलों के बीच लड़ाई नहीं है और न ही सीधा मुकाबला है। यहां इस बार गठबंधन का मुकाबला है। एक ओर जहां महायुति है तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी। दोनों ही गठबंधन में कई दल शामिल हैं। वहीं झारखंड की 81 सीटों पर भी दिलचस्प मुकाबला है। असली नतीजे 23 नवंबर को आएंगे लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। मैट्रिज व अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सकती है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 89-101 सीटें तो वहीं कांग्रेस 39-47 सीटें जीतती हुई दिख रही है। महायुति को 150 से 170 सीटें तो वहीं एमवीए को 110 से 130 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं बात करें झारखंड की तो वहां मैट्रिज समेत अन्य एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बनती दिख रही है।

देश की राजनीति पर भी पड़ेगा बड़ा असर- महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर महायुति की सरकार बन सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल से साफ संकेत मिलते हैं कि महायुति (बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजति पवार की एनसीपी) ने महाविकास अघाड़ी (कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी) को पछाड़कर शानदार सफलता हासिल की है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर जरूर दिखाई जा रही है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है। इससे साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने बंटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं का जो नारा उछाला उसमें महाविकास अघाड़ी की गाड़ी फंस गई। इन नतीजों का महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ने की संभावना है। क्योंकि इससे साफ हो गया कि जनता का मूड क्या है और उसे कौन पसंद है। देखा जाए तो यह नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच लड़ाई थी। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को शानदार टक्कर दी थी और 48 में से 30 सीटें अपने खाते में कर ली थीं। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा और लोकसभा में भी उसकी ताकत कम हो गई। तभी से बीजेपी इस खेल को पलटने में जुटी हुई थी।

झारखंड से हटेगी हेमंत सोरेन की सरकार

झारखंड में मैट्रिज के एग्जिट पोल के आकंड़ों के मुताबिक राज्य में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है और बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। मैट्रिज एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 42-47 पर बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कब्जा जमाने जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25-30 सीटें मिलने का अनुमान है। 1 से 4 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन को 45-50 सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम के यूपीए गठबंधन को 35-38 से लेकर 03-05 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं 3 से लेकर 5 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी लीडिंग एनडीए गठबंधन को राज्य में 40-44 सीटें मिलने की उम्मीद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को यहां 30-40 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को यहां सिर्फ एक सीट मिलने का अनुमान है।

उत्तरप्रदेश में योगी का दमखम बरकरार

उत्तरप्रदेश के सभी नौ सीटों में वोटिंग खत्म होने के बाद सबकी नजरें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं, जिन्हें देखकर यह लग रहा है कि यूपी में सीएम योगी के बंटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का जादू चल गया है। मेट्रीज के सर्वे के मुताबिक यूपी उपचुनाव में बीजेपी के पाले में 7 सीटें आ सकती हैं। जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य पर के खाते में एक भी सीट नहीं आ रही है। टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक, यूपी में बीजेपी के पाले में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी के खाते में 3 तो अन्य को एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है। जी न्यूज के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 5 सीटें, जबकि सपा के खाते में 4, तो वहीं अन्य के खाते में शून्य सीटें मिलने का अनुमान है।

बुधनी और विजयपुर में भी बीजेपी का पलड़ा भारी

मध्यप्रदेश में दो सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को वोटिंग हो गई है। 23 को परिणाम आने हैं। फाइनल रिजल्ट से पहले दोनों सीटों के लिए एग्जिट पोल आए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बुधनी में साफ है कि बीजेपी की वापसी हो रही है। वहीं, विजयपुर में रामनिवास रावत की राह आसान दिख रही है लेकिन हार-जीत के लिए वोटों को अंतर ज्यादा नहीं होगा। स्थानीय जानकारों का भी अनुमान है कि दोनों सीटों पर बीजेपी आ सकती है। इसके पीछे तर्क है कि बुधनी बीजेपी का गढ़ रहा है। साथ ही विजयपुर में भी रामनिवास रावत लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि 23 नवंबर को ही स्थिति साफ हो पाएगी।

महाराष्ट्र में विपक्ष के दावे हुए फेल

लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी। आखिरी वक्त तक यह कह पाना मुश्किल था कि लोकसभा चुनवा में आगे कौन चल रहा है, लेकिन आम चुनाव में कांग्रेस ने विदर्भ का गढ़ एक बार फिर हासिल कर लिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को काफी जोरदार टक्कर मिली। एग्जिट पोल के अनुमान बताते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ताकत विधानसभा चुनाव में बढ़ी है। उसने सभी विपक्षी दावों को नकारते हुए शानदार कामयाबी हासिल की है।

इंदौर-भोपाल आने वाले दिल्ली के यात्रियों को जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना होगा

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) खतरनाक स्तर पर पहुंचने और कोहरे की शुरुआत के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी गई है। इंडिगो ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट और ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया है कि कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित हो रही है, जिससे यातायात धीमा और उड़ानों में देरी हो सकती है। कंपनी ने यात्रियों से निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने, यात्रा की

स्थिति की जांच करने और अतिरिक्त समय लेकर चलने की अपील की है। कोहरे और प्रदूषण के कारण उड़ानों पर असर पड़ रहा है, जिसमें देरी और रद्दीकरण की आशंका बढ़ गई है। इंदौर के लिए इंडिगो की चार फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, और यात्रियों को संभावित दिक्कतों के बारे में पहले से सूचित किया जा रहा है। यह समस्या केवल इंडिगो तक सीमित नहीं है अन्य एयरलाइंस भी इस स्थिति से प्रभावित हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डों पर यात्रियों को सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सलाह जारी की जा रही है। यात्रियों को सुझाव दिया गया है कि वे समय पर अपनी यात्रा की योजना बनाएं और उड़ान से संबंधित अद्यतन जानकारी पर ध्यान दें।

दिल्ली से इंदौर के लिए अभी 9 फ्लाइट

-दिल्ली से इंदौर के लिए अभी अलग-अलग एयरलाइंस द्वारा रोजाना लगभग 9 फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। इंडिगो एयरलाइन दिल्ली से इंदौर के लिए रोजाना चार उड़ान संचालित कर रही है।

-फ्लाइट नंबर 6ई 6212 दिल्ली से सुबह 5.00 बजे इंदौर के लिए उड़ान भर्ती है, जो 6.30 बजे इंदौर एयरपोर्ट पहुंचती है।

-फ्लाइट नंबर 6ई 2016 दिल्ली से सुबह 8.55 बजे उडान भारती है जो की इंदौर एयरपोर्ट पर 10.25 बजे लैंड करती है।

-फ्लाइट नंबर 6ई 902 दिल्ली से शाम को 5.30 बजे उड़ान भर्ती है, जो की 7 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करती है।

-फ्लाइट नंबर6ई 2208 दिल्ली से 9.05 बजे उड़ान भर्ती है, जो की 10.35 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर उतरती है।

दिल्ली से भोपाल के लिए इंडिगो की फ्लाइट

-दिल्ली से भोपाल के लिए कुल 6 फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। इंडिगो एयर लाइन्स चार फ्लाइट का संचालन कर रही है।

-फ्लाइट नंबर 6ई2112 दिल्ली से सुबह 7.05 बजे भोपाल के लिए उड़ान भर्ती है, जो 8.25 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचती है।

- फ्लाइट नंबर 6ई2433 दिल्ली से सुबह 11.20 बजे भोपाल के लिए उड़ान भर्ती है, जो 12.35 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचती है।

- फ्लाइट नंबर 6ई5050 दिल्ली से शाम 6.10 बजे भोपाल के लिए उड़ान भर्ती है, जो 7.30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचती है।

-फ्लाइट नंबर 6ई 894 दिल्ली से रात 8 बजे भोपाल के लिए उड़ान भर्ती है, जो 9.20 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचती है।

तीन दिन में दूसरी बार टिगरिया बादशाह पहुंची निगम की टीम

नंदबाग सड़क के लिए और तोड़े 100 से ज्यादा मकान

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के नंदबाग में नगर निगम ने बुधवार को करीब 110 मकान और तोड़े। इनमें 20 से ज्यादा पक्के निर्माण थे। पांच घंटे में चार पोकलेन और 10 जेसीबी की मदद से ये मकान तोड़े गए। इससे पहले 50 मकान तोड़े गए थे। इस तरह अब तक 160 मकान तोड़े जा चुके हैं। अब सुपर कॉरिडोर-टिगरिया बादशाह से खड़े गणपति मंदिर तक नगर निगम 100 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण अगले माह से शुरू करेगा। अभी सप्ताह भर मलबा हटाने और सड़क साफ करने का काम होगा। बुधवार सुबह आठ नगर निगम की रिमूवल गैंग नंदबाग आई। कुछ रहवासियों से स्वेच्छा से भी मकान तोड़ना शुरू कर दिए थे। पक्के निर्माणों को पोकलेन की मदद से तोड़ा गया। बुधवार दोपहर नगर निगम का अमला वहां पहुंचा और रास्ते में आ रहे मकानों के 1 से 5 फीट तक के अवैध हिस्सों को हटाया। नगर निगम की अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि मकानों के आगे बने अवैध हिस्से को हटाने के लिए नगर निगम ने रहवासियों को पहले से ही नोटिस जारी कर दिए थे। यह अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का हिस्सा है।

रहवासियों ने फिर से किया विरोध

अपर आयुक्त अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को भी कुछ रहवासियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की। हमारे साथ भारी पुलिस बल मौजूद था। इसके साथ ही हमने

उन्हें समझाइश भी दी। इसके बाद निगम के अमले ने सभी 110 मकानों के अवैध हिस्से को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया। इस दौरान एक रहवासी श्यामसुंदर पटेल ने बताया कि हमारा मकान बरसों पुराना है और निगम इसे अवैध बता रहा है। हमने कोई बड़ा कब्जा नहीं किया है,फिर भी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल, नगर निगम ने दो दिन पहले, सोमवार को भी यहां सड़क निर्माण में बाधक बन रहे मकानों को हटाया था। तब कुछ रहवासियों के साथ विवाद की स्थिति बनी थी।

तीन दिन से अनाउंसमेंट किया जा रहा था

निगम अधिकारियों ने बताया कि इंदौर नगर निगम के झोन-4 में आने वाले टिगरिया बादशाह इलाके में बचे हुए मकानों के अवैध हिस्सों को भी हटाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तीन दिन से अनाउंसमेंट किया जा रहा था। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, और वे लोगों से लगातार मिल रहे थे। इसके चलते अधिकांश मकान खाली मिले, जिससे कार्रवाई में परेशानी नहीं हुई। जिन लोगों ने खुद से अवैध हिस्से नहीं हटाए, उन्होंने आज निगम टीम से मदद ली और अपना सामान हटाया।

ट्रैफिक लोड कम करेगी 100 फीट चौड़ी सड़क

तीन साल बाद उज्जैन में लगने वाले सिंहस्थ मेले के समय नंदबाग-टिगरिया बादशाह सड़क बाणगंगा मार्ग और स्वदेशी मिल मार्ग का ट्रैफिक लोड कम करेगी। यह सड़क 100 फीट चौड़ी बनाई जा रही है। इस मार्ग से होकर धार रोड से आने वाला ट्रैफिक सीधे उज्जैन रोड से कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सुपर कॉरिडोर के आसपास की टाउनशिपों को भी मध्य क्षेत्र से यह सड़क चौड़ेगी। अभी तक कॉरिडोर को शहर से जोड़ने के लिए चौड़ी सड़क नहीं है।

20 करोड़ में बनेगी तीन किमी लंबी सड़क

नंदबाग-टिगरिया बादशाह सड़क की चौड़ाई मास्टर प्लान में 100 फीट है। तीन किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण नगर निगम 20 करोड़ की लागत से करेगा। इसके लिए टेंडर भी जारी हो चुके हैं। आठ माह में इस सड़क का निर्माण नगर निगम ने पूरा करने का लक्ष्य रखा है। शहर में लंबे अरसे बाद इतनी बड़ी संख्या में बाधक निर्माण तोड़े गए। इससे पहले गणेशगंज और बियाबानी में बड़े पैमाने पर निर्माण तोड़े गए थे।

20 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिला जाएगा गणपति घाट का बायपास

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। प्रदेश के सबसे बड़े ब्लैक स्पॉट गणपति घाट का बायपास तैयार हो रहा है। अगले माह तक यह ट्रैफिक के लिए खोल दिला जाएगा। आठ किलोमीटर लंबे बायपास से होकर वाहन इंदौर से सेंधवा की तरफ जा सकेंगे। फिलहाल जिस मार्ग से वाहन गुजरते है, वहां ढलान ज्यादा होने से भारी वाहनों के ब्रेक फेल हो जाते थे और वे दूसरे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेत थे। बीते दस सालों में गणपति घाट पर गलत ढलान के कारण 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ज्यादातर हादसों में वाहनों में आग लग जाती है और उसमें सवार लोग बचकर निकल भी नहीं पाते थे। मुबंई आगरा राजमार्ग पर यह घाट मानपुर से आगे आता है। फोरलेन मार्ग का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था। तब यहां पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि 20 दिसंबर तक बायपास पर ट्रैफिक शुरू करने की तैयारी है। नए बाइपास को बनाने में दो साल का समय लगा।

ज्यादातर पुराने भारी वाहन हुए हादसे का शिकार

इस घाट पर ज्यादातर वे भारी वाहन हादसों का शिकार हुए है, जो काफी पुराने होते है। ज्यादातर फर्शी, लोहे के रोल ले जाने वाले हादसे का शिकार होते है,क्योकि ढलान पर उनका लोड आगे की तरफ आ जाता है और स्पीड कंट्रोल करने के लिए जब ड्रायवर ब्रेक लगाते है तो ब्रेक फेल हो जाते है।भारी वाहन आगे चल रहे वाहनों को अपनी चपेट में ले लेते है। टक्कर के बाद भी वाहन नहीं रुकता और घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है।

ढाल गांव से नीमगढ़ तक बन रहा नया बायपास

हादसे वाले घाट पर अगले माह से भारी वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी।

नया बायपास ढाल गांव से नीमगढ़ तक बन रहा है। इसके निर्माण पर डेढ़ सौ करोड़ रुपये की लागत आई है। चार साल पहले इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, लेकिन वन भूमि मिलने व निजी भूमि के अधिगृहण में देरी होने से निर्माण समय पर शुरू नहीं हो सका।

रोजगार मेले में 25 कंपनियों ने 352 युवाओ को किए जॉब ऑफर

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। रोजगार मेले में बुधवार को आई 25 कंपनियों ने 352 युवाओं को नौकरियां दीं। नौकरी पाने वालों में 78 युवतियां, 274 युवक हैं। जिला रोजगार कार्यालय और आईटीआई ने मिलकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नंदानगर में रोजगार मेला लगाया। 596 ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रजिस्ट्रेशन हुए। सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद किया गया। जिला रोजगार कार्यालय के उपसंचालक (रोजगार) पीएस मंडलोई ने बताया कि रोजगार मेले में 25 कंपनियां जॉब ऑफर करने आईं। जस्ट डायल, मोजेक वर्क स्किल, श्याम मोटर, पटेल मोटर, फार्मा ग्रोथ सहित कई कंपनियां इसमें शामिल हैं। 12 हजार से लेकर 25 हजार तक की नौकरी ऑफर की जा रही है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब ऑफर की जा रही है। 18 से 40 तक के लोगों ने इसमें आवेदन किए हैं। मूल रूप से देवास जिले के कमलेश

भावसार ने बताया कि वे इंदौर में गणेश नगर, खंडवा रोड पर रहते हैं। बीए में ग्रेजुएट कमलेश पिछले 2 से 3 महीने से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनका कहना है कि घर से प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता है और वे चाहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। प्रिंस शर्मा बताते हैं कि वे कम्प्यूटर टेक्नीशियन हैं और आईटीआई से डीजल मैकेनिक ट्रेड से हैं। इंदौर के गांधी नगर में रहते हैं। वे यहां कम्प्यूटर टेक्नीशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अलग-अलग कंपनियों में इंटरव्यू दिया हैं। कुछ कंपनी ने गुरुवार को कॉल करने का कहा है। यश भावसार ने बताया कि वे एमबीए बिजनेस इकॉनोमिक्स-फाइनेंस की पढ़ाई कर चुके हैं। बैंक ऑफिस या ऑपरेशन्स में जॉब की तलाश कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरिएंस चाहिए। फिलहाल वे फ्रेशर हैं। एक्सपीरिएंस के लिए और ग्रोथ के लिए नौकरी करना चाहते हैं। आगे वे बैंक में जॉब करना चाहते हैं।

सरकारी स्कूल भवनों में ठहर सकेंगे विहार करने वाले जैन संत

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। मध्यप्रदेश के सभी जिलों में जैन मुनियों के विहार के दौरान स्कूल, सामुदायिक भवनों में ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रदेश में हाईवे और अन्य सड़क मार्गों के किनारे स्थित गांवों और पंचायतों में बने सामुदायिक भवन और स्कूलों में साफ-सफाई पर फोकस किया जाए। यहां ऐसी व्यवस्था की जाए कि इन मार्गों पर पड़ने वाले भवनों को जैन मुनियों के विहार (आवागमन) के दौरान रुकने के लिए दिया जा सके। इसके साथ ही ऐसे स्थानों के आस-पास रिक्त पड़ी सरकारी भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किए जाने की कार्ययोजना तैयार कराई जाए।

यह बात विभाग के कामों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री पटेल ने कहीं। उन्होंने भोपाल-दमोह मार्ग का जिक्र करते हुए कहा कि जब इस मार्ग से जैन मुनि अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ गुजरते हैं तो उन्हें रात्रि होने पर रुकने के लिए उचित भवनों की कमी का सामना करना पड़ता है। जैन मुनियों को रुकने का इंतजाम हो, इसके लिए पंचायतों में मौजूद सामुदायिक भवनों और यहां रोड किनारे संचालित सरकारी विद्यालयों के भवनों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए ऐसे भवनों को चिन्हित कराकर साफ-सफाई, रंगाई-पुताई और पेयजल का इंतजाम कराया जाए ताकि जैन मुनि जब भी कहीं से गुजरें तो इन भवनों में रुक सकें। इस तरह की व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों और मार्ग में करने का निर्देश दिया है।

एमडी ड्रग्स के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा, राजस्थान से लाए थे ड्रग्स

इंदौर. इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने सुपर कॉरिडोर गांधीनगर चौराहे पर एमडी ड्रग्स के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस टीम को एक नीले रंग की स्विफ्ट कार तेज गति से दिलीप नगर चौराहे की ओर जाते दिखी। पुलिस टीम के द्वारा धार की ओर जाने वाली उक्त कार को शासकीय वाहन अड़ाकर रोका और आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। नाम, पता पूछने पर आरोपियों ने अपना नाम इरशाद पिता शेख मोहम्मद निवासी हारुन कॉलोनी खजराना इंदौर, लखन पिता किशोर बैरागी निवासी झालावाड़ राजस्थान, दशरथ पिता रामलाल सेन निवासी झालावाड़ राजस्थान बताया। सभी संदिग्धों की तलाशी लेते समय उनके पास अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स होना पाया गया। इसका कुल वजन 52 ग्राम होना पाया गया जिसके संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया।

लालबाग में 21 हजार बालिकाएं करेंगी महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत पाठ

सिटी चीफ इंदौर।

इंदौर। इंदौर के लालबाग में 24 नवंबर की शाम 4 बजे अनूठा आयोजन होगा। यहां एक हजार कन्याओं का पूजन होगा। 21 हजार बालिकाएं महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत पाठ करेंगी। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक लालबाग परिसर में सेवा मेला लगाया जाएगा। हिन्दू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक गुणवंत सिंह कोठारी, इंदौर चेयरमैन विनोद अग्रवाल, इंदौर अध्यक्ष राधेश्याम शर्मा ने बताया कि युवा शक्ति के चिंतन और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षित और जवाबदारी का भाव विकसित करेंगे।

एक साथ कन्याएं करेंगी पाठ

महिला समन्वयक विनीता धर्म, आईएचएसटीएफ इंदौर अध्यक्ष मंजूषा राजस जौहरी और एचएसएसएफ सदस्य सरस्वती पेंढारकर ने बताया कि भारतीय पारंपरिक परिधानों में सजधज कर बालिकाएं महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत का पाठ एक साथ करेंगी। इसके लिए हर दिन विभिन्न सत्रों में ऑडियो-वीडियो और धार्मिक किताबों के माध्यम से रिहर्सल करवाई जा रही है।

एक साथ एक ही सुर-ताल

एक साथ एक ही सुर ताल में स्त्रोत का पाठ न केवल माहौल को आध्यात्मिकता से जोड़ेगा बल्कि सकारात्मक की लहर भी घोल देगा। आयोजन में 100 कन्याएं मंच पर त्रिशूल के साथ दिखेंगी और मंच के ठीक सामने 1 हजार कन्याओं का पाद-पूजन होगा।

घर-घर पहुंची 21 हजार किताबें

हिन्दू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के प्रचार प्रमुख जवाहर मंगवानी, कार्यक्रम संयोजक अनूप शुक्ला, व्यवस्था प्रमुख दीपक जैन (टीनू) ने बताया रविवार को होने वाले इस कन्या पूजन और महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत पाठ में मठ-मंदिर, एनजीओ सहित कई स्कूल की बालिकाएं शामिल होंगी। अन्य सामाजिक संगठनों का भी इसमें विशेष सहयोग रहेगा। आयोजन के पहले 21 हजार से ज्यादा किताबें घर-घर पहुंचाई जा चुकी है। प्रोग्राम में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे।

प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के आदेश जारी

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। राज्य शासन अगले पांच वर्षों में 2 लाख 50 हजार सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा। पदों की गणना करने के दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिंदु 'रोजगार के अवसर' में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने का संकल्प दोहराया है। इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपरिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचाकिताएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिससे वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया बिना रूकावट पूरी की जा सके।

पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी

राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे। लेकिन पहले जारी आदेशों, परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा 30 अक्टूबर, 2024 तक भर्ती की कार्यवाही कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएगी। इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल, म.प्र. लोक सेवा आयोग/अन्य संस्था को प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है, परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है या परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है।

प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया

मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है। यह परिपत्र वर्ष 2028-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल/एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे। ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा।

इस तरह होगी भर्ती

ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जाएगी (अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे)। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में आधार पर की जाएगी। यदि 33% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि 33% अथवा अधिक है पर 66% से कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46% की पदपूर्ति होगी।

यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66% अथवा अधिक है तो..

यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66% अथवा अधिक है तो वर्षवार पदपूर्ति में, प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% भर्ती होगी। ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पदपूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जाएंगे। सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी। यदि 25% अथवा अधिक है, पर 50% से सीधी भर्ती के रिक्त पद कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी। इसमें प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 46% और तीसरे साल 2026-27 में 46% पदों की पूर्ति होगी। रिक्त पद यदि 50% या उससे अधिक या 75% से कम है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 31%, तीसरे साल 2026-27 में 31% और चौथे साल 2027-28 में 30% पदों की पूर्ति होगी। इसी प्रकार यदि रिक्त पर 75% या उससे ज्यादा है, तो प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, सीधी भर्ती के कुल पद द्वितीय वर्ष 2025-26 में 23% तृतीय वर्ष 2026-27 में 23%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 23%, और वर्ष 2028-29 में 23% पदों पर भर्ती होगी।

डाईंग संवर्गों में भर्ती नहीं

राज्य शासन द्वारा डाईंग संवर्ग घोषित किए जा चुके संवर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। अनुबंधित वाहन के लिए वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं, वे भी वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करें।

समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो

राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति आउटसोर्स पर करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी नीति-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट विभाग जहां चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अतिआवश्यक है, वे वित्त विभाग को तथ्यों सहित प्रस्ताव प्रेषित करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं कि रिक्त पदों की पूर्ति के समय कैडर मेनेजमेंट प्रभावित न हो।

इंतेहा हो गई... आईएएस अफसर का फोन नहीं उठाते जूनियर

माजरा राज्य शिक्षा केंद्र का, सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मध्यप्रदेश में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी का दर्द सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनकी दुखती रग में जब झांका गया तो पता चला कि उनके कार्यालय में ही पदस्थ जूनियर अधिकारी फोन नहीं उठाते, न ही कॉल का जवाब देते हैं। इंतेहा तो यहां तक हो जाती है कि वे फोन तक बंद कर लेते हैं।

यह पूरा माजरा राज्य शिक्षा केंद्र का है। यहां के संचालक द्वारा की जाने वाली फोन कॉल उनके अधीनस्थ अधिकारी अवकाश के दिन नहीं उठाते। इस स्थिति से निपटने के लिए आईएएस अधिकारी हरजिंदर सिंह ने नोटशीट लिख दी। अब इस नोटशीट को कांग्रेस के नेताओं ने मुद्दा बनाकर सरकार पर तंज कसा है।

हरजिंदर सिंह ने नोटशीट में अपना दर्द लिखा है। उन्होंने लिखा कि अवकाश के दिनों में राज्य शिक्षा केंद्र से संबंधित विभागीय गतिविधियों की जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा संचालन को लेकर कोई चर्चा की जाती है तो ऐसे में राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों को समुचित सहयोग नहीं मिल पाता है। नोटशीट में उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसे मामलों में संबंधित वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के नियंत्रकों और को-ऑर्डिनेटर्स को कॉल लगाया जाता है तो इन अफसरों का मोबाइल बंद आता है। अगर मोबाइल चालू भी है तो अधिकारी कॉल अटेंड नहीं करते। ऐसे में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मंत्री और सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को जानकारी नहीं दे पाते हैं।

जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो करनी पड़ेगी कार्रवाई

आईएएस संचालक हरजिंदर सिंह ने आगे लिखा है कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि कार्यालय व्यवस्था संचालन के लिए सभी का सहयोग करना नैतिक दायित्व है। खासतौर पर केंद्र में पदस्थ सहायक संचालक, संयुक्त संचालक, नियंत्रक, समन्वयक की यह जिम्मेदारी भी है। इतना ही नहीं संचालक ने इन लापरवाह अधिकारियों को यह भी कहा है कि अगर अब सभी अधिकारी अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन निष्ठा से नहीं करेंगे और संचालक के रूप में सहयोग नहीं करेंगे, तो कार्रवाई करनी पड़ेगी।

कांग्रेस ने कसा तंज

इस पूरे मामले पर मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार केके. मिश्रा ने सोशल मीडिया पर नोटशीट की फोटो शेयर करते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि सरकार, जब यह असहनीय दर्द एक आईएएस अफसर का है, तो (बे) चारी जनता के हाल क्या होंगे? क्या (सु) शासन, नवाचार, गुड गवर्नेंस की परिभाषा भी यही है।

उन्होंने लिखा है कि यह दस्तावेज मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं, का है। उन्होंने अपनी मार्मिक पीड़ा से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्कूली शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया है।

गूगल सर्च की तरह मंत्रालय में अब एक कमांड पर मिलेंगे पुराने आदेश

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार एक जनवरी से मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही अब मंत्रालय में अब सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग समेत अन्य विभागों के पुराने आदेशों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इन्हें मंत्रालय के लिए गूगल सर्च की तर्ज पर डेवलअप सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस मंत्रालय के अधिकारियों के पास रहेगा। इस सॉफ्टवेयर में किसी भी डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ नाम या जानकारी लिखकर कमांड देनी होगी। इसके बाद उससे संबंधित आदेश/सर्कुलर स्क्रीन पर आ जाएंगे। इससे समय की बचत के साथ ही तुरंत फैसले लेने में मदद मिलेगी। पुराने दस्तावेजों की डिजिटाइजेशन से सरकारी कार्यालयों में आधुनिकता और दक्षता बढ़ेगी। इससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अब तक 20 हजार से ज्यादा दस्तावेज स्कैन हो चुके हैं। दरअसल, अधिकतर सेवाओं और नियम शर्तों से संबंधित आदेश और सर्कुलर सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग निकालते हैं। अभी वित्त विभाग के आदेश स्कैन होना है। इसके अलावा दूसरे विभाग भी अपने विभाग से संबंधित आदेश और जरूरी निदेर्शों को स्कैन कर अपडोल करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया कर सकेंगे।

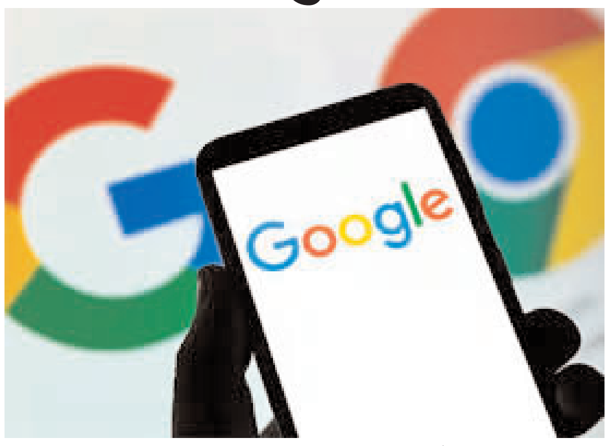

समय की होगी बचत

जीएडी कर्मचारियों से संबंधित आदेश और सर्कुलर समय समय पर जारी करता रहता है। ऐसे में किसी नए निर्णय से पहले उन आदेशों को पढ़ना जरूरी होता है। इन फाइलों की खोजबीन के लिए अधिकारियों को बाबुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें कई बार समय भी लगता है। अब डिजिटाइज्ड डॉक्यूमेंट्स को तुरंत एक्सेस किया जा सकेगा। इससे समय की भी बचत होगी।

दस्तावेजों को सुरक्षित रखना होगा आसन

नई तकनीक से पुराने से पुराने डॉक्यमेंट को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस नई प्रक्रिया में डिजिटल आर्काइविंग के माध्यम से दस्तावेजों को सुरक्षित रखना भी आसान होगा। आग लगने की घटना, किसी प्रकार से दस्तावेजों की अदला-बदली और गुम होने जैसी समस्याएं खत्म होंगी। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।

सीएम डॉ. यादव बोले- औद्योगिक समृद्धि में नंबर वन राज्य बनेगा मध्यप्रदेश

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश मंडप का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, कला और संस्कृति में समृद्ध है। प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग, पावन नर्मदा-शिप्रा नदियां, टाइगर स्टेट, तेंदुआ स्टेट और चीता स्टेट का दर्जा तथा देश का एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण और रोजगारपरक नीतियों के माध्यम से प्रदेश को तेजी से विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और रोड शो के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। एक जिला-एक उत्पाद योजना से महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ भारी उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है। 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। मंडप में प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, स्टार्ट-अप्स, उद्यमों और जन-कल्याणकारी योजनाओं का कलात्मक प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग और माटीकला बोर्ड को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।

मध्य प्रदेश दिवस समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समां बांधा। जबलपुर के जानकी बैंड और बुंदेलखंड के लोक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सरकार की इन पहलों से प्रदेश की औद्योगिक और सांस्कृतिक समृद्धि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

पराली जलाने वालों के केस नहीं लड़ेंगे मध्यप्रदेश के वकील

बार काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कहा है कि पराली जलाने के आरोप में पकड़े गए किसानों का केस उनके वकील नहीं लड़ेंगे। ये फैसला एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष डीके जैन ने बताया कि बैठक में पराली जलाने से होने वाले नुकसान पर चिंता जताई गई। पराली जलाने से लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियां होती हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। एसोसिएशन ने माना कि पराली जलाना एक गंभीर समस्या है। इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। एसोसिएशन ने कहा कि न्यायालय और सरकार ने इस बारे में कई बार चेतावनी दी है। पराली जलाने से खेतों में रहने वाले जीव-जंतु मर जाते हैं। जीव-जंतुओं से खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। पराली जलाने से हवा जहरीली हो जाती है। इससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि पराली जलाने के मामले में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। पराली जलाने की वजह से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में लोग परेशान हैं। एसोसिएशन का मानना है कि लोगों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में पता नहीं है। साथ ही, प्रशासन की लापरवाही की वजह से भी लोग पराली जला रहे हैं। एसोसिएशन ने देश हित में यह फैसला लिया है कि पराली जलाने वाले किसानों का केस नहीं लड़ा जाएगा।

अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराएंगी मुस्कान

सिटी चीफ भोपाल।
भोपाल. पर्वतारोही मुस्कान रघुवंशी अब अफ्रीका के तंजानिया में स्थित सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराएंगी। अशोकनगर की मुस्कान को कलेक्ट्रेट प्रांगण में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और शहर के गणमान्य नागरिकों ने फूल मालाएं पहनाकर और तिरंगा सौंपकर रवाना किया। सीएम मोहन यादव ने मुस्कान को राज्य सरकार की ओर से चार लाख की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। बता दें, राष्ट्रीय के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी अशोकनगर की मुस्कान रघुवंशी ने सबसे पहले साइकिल से नर्मदा परिक्रमा और फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भी यात्रा पूरी की थी। इसके बाद इसी साल ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया था और अब अफ्रीका के दुर्गम पर्वत किलिमंजारो पहुंचकर तिरंगा फहराकर देश का नाम ऊंचा करेंगी।

पुष्प वर्षा कर स्वागत किया

मुस्कान को अशोकनगर से रवाना करने के दौरान उसका उत्साहवर्धन करते हुए मालाएं पहनाकर पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुस्कान ने कहा कि इस पूरी यात्रा में हम कुल आठ लोग हैं, जिनमें से एमपी से मैं अकेली हूं। बाकी अन्य राज्यों से भी लोग इसमें शामिल हैं। वहीं, अपने स्पॉन्सर को धन्यवाद देते हुए मुस्कान कहती हैं कि मुझे काफी सपोर्ट मिला है और मैं चाहती हूं कि ऐसा लीडर हर जगह हो, जो महिलाओं की इतनी मदद करे।

सीएम ने दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पर्वतारोही मुस्कान रघुवंशी को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए चार लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश दिए हैं। मुस्कान अशोक नगर जिले के ग्राम महाना के निवासी रामकृष्ण रघुवंशी की बेटी हैं। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की यह बेटी नई सफलताएं प्राप्त करेगी।

भोपाल से बीपीएड कर रहीं मुस्कान

बता दें, 23 वर्ष की मुस्कान भोपाल के रविन्द्र नाथ टैगोर विश्वविद्यालय से बीपीएड का पाठ्यक्रम कर रही हैं। उन्होंने जब आस्ट्रेलिया के पर्वत की चोटी को छुआ था तो अपने आयु वर्ग में सबसे कम उम्र की पवार्तारोही थीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 24 अगस्त 2024 को चंदेरी प्रवास के दौरान मुस्कान को उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के लिए बधाई दी थी।

सम्पादकीय

जी20 की दो दिवसीय शिखर बैठक में भारत ने दिखाई दिशा

जी20 शिखर बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा मेजबान ब्राजील की ओर से शुरू किया गया 'भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता' का अभियान, जिसे 80 देशों का समर्थन पहले ही मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की खुली वकालत करते हुए इसे नई दिल्ली शिखर बैठक में फूड सिक्यॉरिटी के लिए अपनाए गए सिद्धांतों पर अमल का प्रयास बताया। भुखमरी और गरीबी के ही संदर्भ में ग्लोबल साउथ का मसला उठाते हुए पीएम मोदी ने ध्यान दिलाया कि दुनिया में चल रहे युद्धों की वजह से खाद्य, तेल और उर्वरक संकटों का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है।

ब्राजील के रियो द जनेरियो में हुई जी20 देशों की दो दिवसीय सालाना शिखर बैठक जिन कठिन हालात के बीच हो रही थी, उनके मद्देनजर यह कोई तात्कालिक उपलब्धि दिखा पाने में भले सफल नहीं हुई, लेकिन निरंतरता में देखा जाए तो इसने दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों से जूझने के संकल्प को कमजोर नहीं होने दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक चुनौतियों को भारत के नजरिये से जोड़ कर जिस तरह से उनके संभावित हल की दिशा स्पष्ट की, वह खास तौर पर ध्यान देने लायक रहा। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहा मेजबान ब्राजील की ओर से शुरू किया गया 'भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता' का अभियान, जिसे 80 देशों का समर्थन पहले ही मिल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की खुली वकालत करते हुए इसे नई दिल्ली शिखर बैठक में फूड सिक्यॉरिटी के लिए अपनाए गए सिद्धांतों पर अमल का प्रयास बताया। भुखमरी और गरीबी के ही संदर्भ में ग्लोबल साउथ का मसला उठाते हुए पीएम मोदी ने ध्यान दिलाया कि दुनिया में चल रहे युद्धों की वजह से खाद्य, तेल और उर्वरक संकटों का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ा है। ध्यान रहे, भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आवाज सबसे प्रभावी अंदाज में उठाता रहा है। जी20 जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर औपचारिक एजेंडे में हो या न हो, ग्लोबल गवर्नेंस की स्थिति को बेहतर बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार सुनिश्चित करने के मुद्दे को उठाना जरूरी इसलिए है कि कई बड़े देश इन मसलों पर सार्थक चर्चा से बचने की कोशिश करते हैं। हालांकि दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए जरूरी है कि इन वैश्विक संस्थाओं को बदले हालात के अनुरूप ढालने की जिम्मेदारी से आंखें न चुराई जाएं। अच्छा है कि पीएम मोदी वैश्विक नेताओं को इस जिम्मेदारी की याद दिलाने से नहीं चूके। कुछ ऐसे भी मसले रहे जिन पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। खासकर क्लाइमेट चेंज पर शिखर बैठक की ओर से जारी साझा बयान में क्लाइमेट फाइनेंस को बिलियंस से ट्रिलियंस करने की बात जरूर कही गई, लेकिन यह पैसा कौन देगा, इस बारे में कोई संकेत तक नहीं किया गया। यूक्रेन युद्ध और गाजा-लेबनान युद्ध पर औपचारिकता निभाने से ज्यादा की तो जी20 बैठक से उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। बहरहाल, ऐसे कठिन दौर में दुनिया की 85 फीसदी संपत्ति कवर करने वाले जी20 देशों का वैश्विक चुनौतियों से आंखें मिलाते हुए उनसे निपटने की प्रतिबद्धता बनाए रखना एक ऐसी बात है जो बेहतर भविष्य की उम्मीदों को जिंदा रखती है। जी20 शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गरीबी और भूख से निपटने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 'सामाजिक समावेशन और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई' सेशन में बोलते हुए प्राधनमंत्री मोदी ने इन मुद्दों को हल करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि देश कैसे पारंपरिक और नए तरीकों के माध्यम से टिकाऊ विकास की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार भारत की दृष्टि दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है- बुनियादी बातों पर वापसी और भविष्य की ओर बढ़ना। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देना और जलवायु-अनुकूल फसलों की खेती की भी चर्चा की। पीएम ने श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने की बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर भी पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत केवल विकास पर ही ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह विकास सभी के लिए समावेशी हो। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया है, जो देश के भूख और खाद्य सुरक्षा को दूर करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

स्ट्रॉन्ग समझे जानें वाले पुरुषों की 'आत्महत्या दर' सबसे ज्यादा क्यों?

देश में आत्महत्या के पिछले एक दशक के आंकड़े उठाकर देखें तो साफ पता चलता है कि इसमें पुरुषों, विशेषकर विवाहित पुरुषों के मामले अधिक रहते हैं। एनसीआरबी के साल 2015 में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आकलन में विशेषज्ञों ने पाया था कि शादीशुदा महिलाओं की तुलना में विवाहित पुरुषों के आत्महत्या की आशंका अधिक होती है। पुरुषों के कुल आत्महत्या के केस में विवाहितों की संख्या सबसे अधिक 66 फीसदी, अविवाहित 21त्न जबकि विधुर-तलाकशुदा की संख्या 3त्न है।

© Getty

लखनऊ के रमन चौहान (बदला हुआ नाम) लाफ्टर क्लब चलाते हैं, जहां मन को स्वस्थ रखने के लिए 'लाफिंग योग' करने रोजाना बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। 2015 में रमन की शादी हुई, घर की हल्की-फुल्की नोक-झोक धीरे-धीरे मानसिक तनाव का रूप लेने लगी। 2019 में रमन ने रोज-रोज की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या का प्रयास किया, शुक्र है कि उनकी जान बच गई। इसी तरह से शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या के मामले पिछले एक दशक में काफी तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों में बढ़ते आत्महत्या को रोकने के लिए दिशा-निर्देश बनाने और पुरुषों की आवाज उठाने के लिए 'नेशनल कमीशन फॉर मेन' के गठन की मांग की गई। अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी द्वारा दायर याचिका में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने आत्महत्या की, इनमें से 81,063 लोग विवाहित पुरुष, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थीं।

पुरुषों में बढ़ते आत्महत्या के आखिर क्या कारण हैं? क्या इसकी एक वजह यह है जिसमें वर्षों से हम मानते चले आ रहे हैं कि 'मर्द को दर्द नहीं होता'? या फिर फेमिनिज्म की मौजूद 'मोडिफाइड अवधारणा' पुरुषों के दमन पर केंद्रित है, जिसमें हमेशा हाशिए पर पुरुष ही होता है? या फिर कुछ और?

देश में आत्महत्या के पिछले एक दशक के आंकड़े उठाकर देखें तो साफ पता चलता है कि इसमें पुरुषों, विशेषकर विवाहित पुरुषों के मामले अधिक रहते हैं। एनसीआरबी के साल 2015 में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आकलन में विशेषज्ञों ने पाया था कि शादीशुदा महिलाओं की तुलना में विवाहित पुरुषों के आत्महत्या की आशंका अधिक होती है। पुरुषों के कुल आत्महत्या के केस में विवाहितों की संख्या सबसे अधिक 66 फीसदी, अविवाहित 21त्न जबकि विधुर-तलाकशुदा की संख्या 3त्न है। आत्महत्या के कारणों में, पारिवारिक समस्याओं को सबसे ऊपर रखा गया है। पारिवारिक कलह और झगड़ों के चलते जहां साल 2014 में 18 हजार पुरुषों ने जान गंवाई वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा 9,900 था। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में आत्महत्या के मामले सिर्फ भारत में अधिक हैं, वैश्विक आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं। यूके में वैसे तो साल 1981 के बाद से पुरुष आत्महत्या दर में काफी सुधार है, प्रति एक लाख पर करीब 15.5 मौतें, लेकिन आत्महत्या अभी भी 45 वर्ष से कम आयु के पुरुषों में मौत का एक प्रमुख कारण है, महिलाओं में यह आंकड़ा केवल 5 है। महिलाओं की तुलना में, ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों की आत्महत्या दर तीन गुना, अमेरिका में 3.5 गुना, रूस-अर्जेंटीना में चार गुना से अधिक है।

अमेरिकन फाउंडेशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे मनोवैज्ञानिक जिल हरकावी-फ्रीडमैन कहते हैं, पुरुषों में अधिक आत्महत्या के मामलों का ट्रेंड लंबे समय से देखा जाता रहा है। इसमें पुरुषों के आत्महत्या के तरीकों पर भी गौर करना जरूरी है। आत्महत्या का प्रयास में पुरुष-महिला दोनों के तरीके को देखें तो पता चलता है कि पुरुष आत्महत्या के तरीके अकसर अधिक हिंसक होते हैं, जिसमें किसी के हस्तक्षेप करने से पहले मृत्यु की आशंका भी अधिक होती है। इसका एक कारण आत्महत्या के साधनों तक आसान पहुंच है, दूसरा- अपने दर्द को व्यक्त न कर पाने के कारण पुरुषों की मानसिक स्थिति भी गंभीर देखी जाती रही है। अपनी भावनाओं को खुलकर न व्यक्त कर पाना, रोकर अपने दुख को न निकाल पाना, लोगों से मदद मांगने में हिचक और सबसे गंभीर बात समाज में पुरुषों को लेकर बनी सोच, जिसमें उन्हें हमेशा 'मजबूत' मानकर चला जाता रहा है, जिसका दबाव हर पुरुष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में करता है, यह भी विचारणीय है। देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी पुरुषों में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों के पीछे के कारण और मानसिकता को समझने के लिए हमने वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ सत्यकांत त्रिवेदी से बातचीत की। डॉ सत्यकांत 'से यस टू लाइफ' कैंपेन के साथ आत्महत्या रोकथाम को लेकर कैंपेन चला रहे हैं और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आत्महत्या रोकथाम ड्राफ्ट के लिए गठित टीम के सदस्य हैं। डॉ सत्यकांत कहते हैं, पुरुषों, विशेषकर विवाहित पुरुषों में आत्महत्या के लिए सामाजिक अवधारणाएं एक प्रमुख कारण हो सकती हैं, जिसकी शुरूआत जाने-अनजाने बचपन से ही हो जाती है। यह कहना बहुत सरल है कि महिलाएं अपनी समस्याओं को आसानी से साझा कर लेती हैं और पुरुष उन्हें अपनी शकभर बोतलबंद रखते हैं। इसके पैरेलल यह भी सच है कि सदियों से समाज ने पुरुषों को मजबूत होने के लिए प्रोत्साहित किया है और इस अनावश्यक कोशिश में पुरुषों की भावनाओं का हमेशा से दमन होता आ रहा है। यह अकसर बचपन में शुरू होता है। हम लड़कों को बताते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, अगर कोई लड़का रोता है तो उसे ताने दिए जाते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? बचपन से इस तरह की बातें सुन-सुनकर लड़कों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि आंसू निकलना हमारे जीवन के शब्दकोश का हिस्सा ही नहीं है, लिहाजा वह दर्द में भी रोने से बचते हैं।

वहीं दूसरी तरफ पुरुषों-महिलाओं का मस्तिष्क और भावनाएं कुदरत ने एक जैसी ही बनाई हैं। महिलाएं आंसू के जरिये आसानी से अपनी समस्याएं व्यक्त कर लेती हैं, और पुरुष वही आंसू घूंट कर रह जाते हैं। यह घूंटना, दिमाग के कोने में बना रह जाता है जो एक समय गंभीर रूप ले लेता है। यही कारण है कि किसी एक ही भावनात्मक स्थिति में पुरुष-महिला दोनों को रखा जाए तो महिलाएं उसे बेहतर ढंग से डील कर लेती हैं। उदाहरण के लिए ब्रेकअप के तनाव से लड़कियां बहुत जल्द निकल आती हैं, वहीं लड़कों के लिए यह उतना ही कठिन टास्क होता है।

बचपन की परवरिश का भावनात्मक रूप से क्या असर होता है, इस बारे में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के एक अध्ययन प्रकाशित हुआ जिसमें शोधकर्ताओं ने बताया कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में बचपन से ही भावनात्मक संवाद का अभाव होता है। इसका असर हमेशा बना रहता है।

मेडिकल परामर्श (उदाहरण के लिए अवसाद के लिए इलाज कराने की दर) को लेकर भी, इस बात का मूल्यांकन किया गया कि मानसिक रोगों के लिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों के मनोचिकित्सकों से मिलने की दर भी 8 फीसदी कम थी, क्योंकि पुरुष तो मानता चला आ रहा है कि वह 'स्ट्रांग'है।

इसी विषय को लेकर कनाडा में सेंटर फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के कार्यकारी निदेशक मारा ग्रुनौ कहते हैं कि हम अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं और उन्हें संवाद करने के लिए कैसे प्रोत्साहित करते हैं, इसका भी भावनाओं पर असर होता है। माताएं अपने लड़कों की तुलना में लड़कियों से ज्यादा बात करती हैं, वे आपस में भावनाओं को साझा कर लेते हैं। हम महिलाओं से भावनात्मक होने की उम्मीद भी करते हैं। वहीं लड़का पिता से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाता है, ऐसे में लड़कों के पास अपने विचारों-भावनाओं को शेयर करने के लिए माता-पिता दोनों का अभाव होता है। बचपन की इस आदत का ताउम्र असर बना रहता है।

निष्कर्ष में डॉ सत्यकांत कहते हैं, इस तरह से बचपन-किशोरावस्था में लड़कों में भावनाओं को दबाने की आदत बनी रह जाती है, जो विवाह के बाद अगर तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है, तो उसमें भी देखी जाती है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों के लिए यह मजबूत आधार है, जिसमें विशेष सुधार ही आवश्यकता है। पुरुष क्यों रो नहीं सकता, इसको पुरुषत्व से जोड़कर क्यों देखा जाता रहा है यह सोच के परे हैं। इसके अलावा समाज में जेंडर बायस्ड सोच, अवधारणाएं भी पुरुषों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों का एक कारण मानी जा सकती हैं, जिसपर भी अब चर्चा करना जरूरी है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि महिलाओं के साथ समाज में अन्याय होता आया है, शोषण-बलात्कार से लेकर मानसिक प्रताड़ना तक, अ'सर ऐसे मामले अखबारों की सुर्खियां रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षित माहौल और समानता का अधिकार मिल सके, इसके लिए उनके पक्ष में कई कानून भी बने हैं। पर इसके पैरेलल इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इन कानूनों का रंजिश या बदले के भाव से गलत इस्तेमाल भी होता आ रहा है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले तीन साल के भीतर झूठे मामले दर्ज कराने वाली लड़कियों-महिलाओं के खिलाफ 50 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। स्थानीय पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई कर रही है, जिसमें झूठा आरोप लगाने वाले को 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। साल 2021 में जहां महिलाओं द्वारा 220 केस दर्ज किए गए जिसमें से 87 को झूठा पाकर कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 2022 में 178 मामले दर्ज हुए जिसमें से 67 को रद्द किया गया है।

ट्रम्प की जीत भारत की कूटनीतिक सफलता!

अमेरिका में रिपब्लिकल पार्टी की ऐतिहासिक विजय के बाद अब यह तय हो गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका का इतिहास बताता है कि ट्रम्प की यह जीत उनकी ऐतिहासिक वापसी है। अमेरिका में यह विजय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 130 वर्ष के अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार है, जब किसी ने यह कारनामा किया है। डोनाल्ड ट्रम्प ने लगातार तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसमें पहली और तीसरी बार वे सफल रहे, दूसरी बार के चुनाव में जो बाइडेन से पराजित हो गए। इस चुनाव में पराजित होने के बाद ट्रम्प अमेरिका में राजनीतिक तौर पर लगातार सक्रिय रहे। उनका मिशन फिर से राष्ट्रपति बनना ही था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम देकर एक नया कीर्तिमान बना दिया। चुनाव में उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस यकीनन राजनीतिक समझ रखती थी, लेकिन यह समझ किसी भी प्रकार से सफलता की परिचायक नहीं बन सकी। हालांकि अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग ने तो उनको भावी राष्ट्रपति के रूप में प्रचारित कर दिया। लेकिन यह नैरेटिव भी उनके लिए जीत का मार्ग नहीं बना सका। यहां एक खास तथ्य यह भी माना जा सकता है कि कमला हैरिस को भारतीय मूल का बताने का सुनियोजित प्रयास किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि भारतीय मूल के मतदाताओं को उनके पक्ष में लाया जा सके, लेकिन वे जिन हाथों में खेल रही थी, वह लाइन भारत के लिए राजनीतिक तौर सही नहीं थी।

वैश्विक राजनीति के जानकार डोनाल्ड ट्रम्प की जीत कई निहितार्थ निकाल रहे हैं। कई विश्लेषक ट्रम्प की जीत को भारत की कूटनीतिक सफलता के तौर पर भी स्वीकार कर रहे हैं। इसका एक कारण यह माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत सरकार जिस नीति और विचार को लेकर कार्य कर रही है, उसकी झलक ट्रम्प के विचारों में भी दिखाई देती है। इसके अलावा ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका की खोई ताकत को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आज अमेरिका कहने मात्र को ही महाशक्ति है, लेकिन उसका वैसा दबदबा आज नहीं है, जो पहले हुआ करता था। इस बीच भारत ने महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्र गति से अपने कदम बढ़ाए हैं, इसलिए आज विश्व के अनेक देश भारत को महाशक्ति के रूप में देखने लगे हैं। हमें स्मरण होगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के दौरान भारत के नागरिक पूरे सम्मान के साथ भारत लौटे थे। उस समय भारत के नागरिकों के समक्ष यूक्रेन की सेना ने अपने हथियार नीचे कर लिए थे। यह केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि भारत की शक्ति का ही परिचायक था। भारत की इस बढ़ती शक्ति से अमेरिका भी भली भांति परिचित है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बारे में कई बार यह कहा जा चुका है कि भारत चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। इसका तात्पर्य यही है कि आज का भारत विश्व के लिए एक ताकत बन चुका है।

अमेरिका के इस चुनाव में भारत के लोकसभा चुनाव की तरह ही प्रचार किया गया। कई प्रकार के नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किए गए। वामपंथी विचार के मीडिया ने ट्रम्प की राह में अवरोध पैदा करने के भरसक प्रयास किए। यहां तक कि उनको सनकी और विलेन कहने में भी गुरेज नहीं किया गया। यही तो भारत में किया गया। वामपंथी समूह ने भारत के लोकसभा चुनावों में सरकार के विरोध में जहरीली भाषा का प्रयोग किया। फिर भी आखिरकार नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। अब ऐसा लगने लगा है कि मतदाता बहुत समझदार हो गया है। उसको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं किया जा सकता। उसे अब देश दुनिया की समझ हो गई है, इसलिए वह वर्तमान के साथ कदम मिलाकर चलने की ओर अग्रसर हुआ है। विश्व के कई देश आज कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना के बाद कई देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, उसे पटरी पर लाने के लिए उस देश की सरकार की ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

आखिर क्यों बढ़ रहा 'नींद में तलाक' का ट्रेंड?

आजकल के शादीशुदा जोड़ों के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसकी सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसे स्लीप डिवोर्स, यानी कि नींद में तलाक का नाम दिया जा रहा है। पूरी दुनिया के समाज शास्त्री और मनोवैज्ञानिक इसको लेकर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। यह सिंड्रोम यानी विकार कॉर्पोरेट कल्चर के वर्क कल्चर के कारण अपने देश में भी फैल चुका है। हमारे बड़े शहरों में इन दिनों खास तौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर रहे अनेक युवा कपल्स अपनी नींद को तरजीह देते हुए स्लीप डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लीप डिवोर्स का मतलब है कि पार्टनर्स अलग-अलग बिस्तर पर सोना शुरू कर देते हैं, ताकि उनकी नींद खराब न हो और वे पूरी नींद ले सकें। लेकिन कपल्स के आपसी रिश्ते, सेक्स लाइफ और करीबी को लेकर अनेक विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। आइए इस मुद्दे का गहन विश्लेषण करें। स्लीप डिवोर्स में पार्टनर ब्रेकअप या तलाक के फेर में नहीं जाते, बल्कि एक ही घर में रहते हुए अलग-अलग सोना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक-दूसरे को परेशान किए बिना पार्टनर रातों को चैन की नींद सो सकें। स्लीप डिवोर्स के दौरान अकसर कपल्स भावनात्मक लेवल पर अलग नहीं होते, बल्कि अपनी नींद पूरी करने के लिए एक-दूसरे से अलग सोते हैं। स्लीप डिवोर्स शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ, यह ठीक-ठीक कह पाना मुश्किल है। लेकिन 2013 से ही इस शब्द को मीडिया में पढ़ा जा सकता है।

अच्छी नींद और सेहत से जुड़े कई हालिया शोधों में भी यह समस्या तेजी से उभरकर सामने आई है। कई विशेषज्ञ अच्छी सेहत को अच्छी नींद से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि स्लीप डिवोर्स से न सिर्फ रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि सेहत भी सुधरती है। स्लीप डिवोर्स या फिर नींद में तलाक का मतलब, असल में एक-दूसरे से अलग हो जाना या तलाक ले लेना नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टनर्स क्वालिटी स्लीप लेने के लिए अलग सोना पसंद करते हैं। इसके अलावा, अलग-अलग स्लीपिंग शेड्यूल होने के चलते, दूसरे पार्टनर के नींद में हाथ-पैर चलाने के कारण, खर्राटे लेने की आदत के चलते या कोई स्लीप डिसोर्डर के कारण स्लीप डिवोर्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन, अच्छी नींद स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है और इसीलिए बहुत से पार्टनर्स यह मानते हैं कि स्लीप डिवोर्स उनके लिए फायदेमंद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश निवासी एक महिला ने कुछ वक्त पहले तो इस समस्या से जूझ रहे पति से तलाक की अर्जी ही कोर्ट में दाखिल कर दी। काउंसलर्स के लाख समझाने पर महिला तलाक लेने पर ही अड़ी रही। महिला के पति को दरअसल खर्राटे बहुत आते थे। महिला ने तलाक का कारण पति के खर्राटों की वजह से उसे होने वाला मानसिक तनाव प्रमुख वजह बताई थी। इंटरनेशनल हाउसवेयर्स एसोसिएशन ने जनवरी 2023 में एक सर्वे किया था। पता चला कि अमेरिका में तो 20 फीसदी जोड़ों ने एक साथ सोना ही छोड़ दिया, जिसके पीछे प्रमुख वजह पति या पत्नी में से किसी न किसी एक को खर्राटों की समस्या थी। सेंट मैरी यूनिवर्सिटी की मनोवैज्ञानिक डॉ. स्टेफनी जे. विल्सन द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जब दो लोग नींद से वंचित होते हैं, तो इससे शरीर में सूजन की प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, और जोड़े एक-दूसरे के साथ अधिक आक्रामक तरीके से और अकसर झगड़ने लगते हैं। यह कितना सच है? स्लीप डिवोर्स को कई लोग अच्छा नहीं मानते हैं। हम इसकी वकालत तो नहीं कर सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नींद में तलाक के फायदे अनेक हैं, क्योंकि कई बार नींद पूरी न होने के कारण चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अगर कपल अलग-अलग सोते हैं तो उनकी नींद पूरी होती है। ऐसे में उनकी हेल्थ भी अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कपल्स के बीच में पर्सनल स्पेस बेहद जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में वह खुद के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। ऐसे में जब वह अकेले सोते हैं तो उन्हें काफी अच्छा महसूस होता है। क्या यह सच नहीं है कि हर एक व्यक्ति का एक स्लीप रूटीन होता है। यह स्लीप का रूटीन कई बार पार्टनर से मैच नहीं करता है, जिसके कारण उनके रिलेशन में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। जब वे अलग-अलग सोते हैं, उनके बीच झगड़े भी कम होते हैं। हालांकि, कई बार कपल्स बिना लड़ाई के भी अलग-अलग सोते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि वो अलग इसलिए सोते हैं ताकि वे अच्छी नींद ले सकें। आसपास के लोगों को लगता है कि कपल्स के बीच लड़ाई है। तभी वे अलग-अलग सोते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मनोचिकित्सक कहते हैं की स्लीप डिवोर्स रिश्ते को ज्यादा बेहतर बनाता है। डिवोर्स शब्द सुनते ही हमारे मन में दो व्यक्तियों के बीच अलगाव होने की छवि उभती है, लेकिन स्लीप डिवोर्स में ऐसी कोई बात नहीं। अलग-अलग सोने का बस यही मतलब है कि आपकी नींद की जरूरतें आपके साथी की जरूरतों से मेल नहीं खाती हैं। इसमें संबंधों में कुछ भी अटपटा नहीं है और यह सामान्य है। असल में, अपने पति या पत्नी से अलग दूसरे कमरे में या अलग बिस्तर पर सोना ताकि रात में वह शांति से चैन की नींद ले सके, इसी स्लीप यानी नींद की अवधारणा को स्लीप डिवोर्स कहा जाता है। नींद में तलाक के नुकसान भी हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का यह विपरीत मत है कि स्लीप डिवोर्स के कारण कपल्स के बीच दूरियां आ सकती हैं। अगर वे अपने कनेक्शन को बनाए रखने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं ढूंढते हैं, तो स्लीप डिवोर्स के कारण, उनके रिश्ते में दूरी पैदा हो सकती है। एक साथ सोने से टचिंग, किसिंग, कडलिंग और स्पूनिंग पार्टनर के साथ रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। नींद में तलाक के दौरान व्यक्ति पहले पहल पार्टनर को मिस करने लगता है और फिर उसी रूटीन को फॉलो करने लगता है। इससे सेक्सुअल लाइफ प्रभावित होती है, जिससे कुछ लोग तनाव का सामना करने लगते हैं। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि जो जोड़े एक साथ बिस्तर शेयर करते हैं, उनमें मनमुटाव या विवाद के सुलझने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। जबकि अलग-अलग सोने वाले जोड़े एक ही मुद्दे पर लंबे समय तक झगड़ते रह सकते हैं। ऐसे में रिश्ता टूटने या किसी एक या दोनों के कहीं और स्पेस तलाशने का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। स्लीप डिवोर्स तभी बेहतर तरह से काम कर सकता है, जब दोनों पार्टनर्स की इस पर सहमति हो। दोनों में ढेर सारा प्यार और एक-दूसरे पर विश्वास हो। ऐसा न होने पर रिश्ते की नींव डगमगा सकती है। यह किसी भी नजरिये से श्रेयस्कर नहीं है। अंत में बकौल शायर 'बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है।' भारतीय समाज में अगर इस परंपरा को अपनाया जाता है, तो कपल्स को सोच-समझकर ही निर्णय लेना चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते से गढ़वाल समाज के उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल की चर्चा सफल रहा

लाकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ बालाघाट, रविवार 17 नवंबर को नागपुर रवि भवन में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ अखिल भारतीय गढ़वाल समाज का उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के संदर्भ में उच्च स्तरीय चर्चा एवं प्रस्ताव रखकर आगामी 5 साल की कार्य योजना को सफल करने का माननीय श्री कुलस्ते जी की ओर से ठोस आश्वासन गढ़वाल समाज ने लिया। गढ़वाल समाज द्वारा महाराष्ट्र में किसी विशेष अभियान में व्यस्तता से समय मिलते ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के विदर्भ अंचल के प्रभारी बनकर नागपुर में पहुंचे श्री फग्गनसिंह कुलस्ते का नागपुर में आगमन होने की जानकारी महाराष्ट्र राज्य गढ़वाल समाज के अध्यक्ष श्री प्रकाश आर अर्जुनवार को मिलते ही उन्होंने सुबह-सुबह अपने मोबाइल से फोन मिलाकर बात किया और नागपुर में तत्काल एक गढ़वाल समाज के उच्च स्तरीय मंडल की भेंट वार्ता की आग्रह पुर्वक इच्छा प्रकट की और बदले में श्री कुलस्ते जी ने श्री प्रकाश अर्जुनवार को अपने निवास में विशेष वार्ता के लिए आमंत्रित किया। रविभवन कॉटेज नागपुर में श्री कुलस्ते जी के साथ अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा के अध्यक्ष श्री रविंद्र नागेश्वर,अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा के उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य गढ़वाल समाज के अध्यक्ष विश्व शांतिदूत प्रकाश आर अर्जुनवार,अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष तथा वर्तमान सक्रिय सामाजिक नेता श्री राजेश नागवंशी,अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा के संरक्षक तथा नागपुर महानगर गढ़वाल समाज मंडल अध्यक्ष श्री रामकुमार बंशपाल, महाराष्ट्र राज्य गढ़वाल समाज कोषाध्यक्ष श्री दुर्गाप्रसाद शिववंशी नागपुर महानगर गढ़वाल समाज मंडल उपाध्यक्ष व युवा नेता श्री कुलदीप परिमल व निलेश भारद्वाज इत्यादि सहित सामाजिक मित्र श्री विनय मिश्रा जी प्रमुख रूप से गढ़वाल समाज के इस उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल में उपस्थित थे। शिष्ट मंडल का विषय था गढ़वाल समाज का समग्र विकास होने हेतु एक उचित प्रयास। सभी पदाधिकारियों द्वारा श्री कुलस्ते जी से अभिवादन और अनौपचारिकता निभाने के पश्चात देश के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री फग्गनसिंह कुलस्ते से गढ़वाल समाज के सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अहम् अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश अर्जुनवार ने सीधा गढ़वाल समाज के विकास संदर्भ में बात करते हुए श्री कुलस्ते जी पर आरोप लगाया की आप अपने देश के कोने कोने में अनेक समाज जाति के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया लेकिन आपके चुनाव क्षेत्र में रहने वाले बालाघाट - सिवनी जिला में बड़ी संख्या में रहने वाला गढ़वाल समाज के किसी भी एक व्यक्ति को भी अपने राजनीतिक, सामाजिक,शैक्षणिक,खेल या आर्थिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ाया।आपने गढ़वाल समाज का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वोटर के रुप में उपयोग किया है और समाज की तरफ दुर्लक्ष किया है। परंतु मेरा और हमारे गढ़वाल समाज का आपसे आग्रह पुर्वक निवेदन है हमारा गढ़वाल समाज बालाघाट और सिवनी क्षेत्र में जनसंख्या के मामले में और आजादी के आंदोलन के मामले में राजनीतिक क्षेत्र के मामले में किसी भी समाज से खास तौर पर मरार समाज, पवार समाज, लोधी समाज और किसी भी समाज से पीछे नहीं है। ऐसे में हमारे समाज के लोग बालाघाट आगामी आगामी विधानसभा चुनाव में गढ़वाल समाज द्वारा बालाघाट विधानसभा तथा परसवाड़ा विधानसभा के साथ-साथ सिवनी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में अपनी दावेदारी मजबूती के साथ रखने वाला है। अतः आप गढ़वाल समाज के प्रत्याशियों को गढ़वाल समाज के विकास के लिए गढ़वाल समाज का नेतृत्व करने और समाज के लोगों का राजनीति में टिकट दिलाने में सिफारिश करना आवश्यक है। इस प्रकार जिला पंचायत की टिकट सिवनी जिला तथा बालाघाट जिला में 10-10 टिकट दिलाने में आपकी राजनीतिक सहायता मिलना आवश्यक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र राज्य में गढ़वाल समाज को ओबीसी का आरक्षण दिलाने तथा मध्य प्रदेश में गढ़वाल समाज को समाज के चाहने पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में से कोई एक जाति का आरक्षण दिलाने का उच्च स्तरीय प्रयास कर गढ़वाल समाज को सामाजिक व राजनीतिक मदद व सहायता करना आवश्यक होगा।

इस पर श्री फग्गनसिंह कुलस्ते जी ने कहा की आपके गढ़वाल समाज के योग्य व उचित कार्यकर्ता और नेताओं को बालाघाट और परसवाड़ा विधानसभा में तथा जिला जिला पंचायत में सक्रियता से काम में लगाओ तथा जीत के आने लायक स्थिति बनने पर मैं गढ़वाल समाज के प्रत्याशियों का दिल खोलकर समर्थन करूंगा। इस प्रकार महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में जाति के आरक्षण दिलाने के लिए राज्य और केंद्र में भरसक प्रयास करूंगा ताकि गढ़वाल समाज के लोगों की समस्या मेरे द्वारा दूर होने पर मुझे बेहद खुशी होगी। मैं गढ़वाल समाज के समग्र विकास के लिए हर संभव सहायता करने की कमी नहीं करूंगा ऐसा ठोस आश्वासन श्री कुलस्ते जी ने गढ़वाल समाज के उच्च स्तरीय शिष्ट मंडल को दिया। भेंटवार्ता एवं चर्चाओं में माननीय श्री कुलस्ते जी द्वारा गढ़चिरोली जिला सहित विदर्भ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों, मध्य प्रदेश तथा केंद्रीय स्तर तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उल्लेखनीय कार्यों और परिदृश्य की चर्चा करते हुए महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन सरकार बनने का विश्वास दिलाया। शिष्ट मंडल में उपस्थित श्री रविंद्र नागेश्वर, राजेश नागवंशी, श्री रामकुमार बांसपाल, श्री कुलदीप परिमल, श्री दुर्गा प्रसाद शिवांशी, नितेश भारद्वाज ने केंद्रीय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री फग्गनसिंह कुलस्ते जी को विविध समस्या बताकर गढ़वाल समाज का सरकारी स्तर पर नेतृत्व व सहायता करने का हार्दिक आवाहन किया।

294 आवेदनों और 22 पुनावृत्ति आवेदनों पर हुई जन सुनवाई

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने गेट पर ही सुनी लोगों की समस्याएं

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर कार्यालय में आज जिले भर से आये नागरिकों ने अपनी समस्याएं जनसुनवाई में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के समक्ष रखी, इस दौरान 22 पुनरावृत्ति आवेदन और सामान्य जनसुवाई में 294 आवेदनों पर सुनवाई करते हुये कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा उस समय मंत्री अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो रहे थे, तब हम सभी लोग गेट पर ही थे और बहुत सारे आवेदक थे। आज एक बहुत बड़ी संख्या में लोग आये, इसलिये गेट पर ही सुन लेना ज्यादा उचित लगा, तो वहीं पर जनसुनवाई की गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी आ रहे थे, उनकी आगवानी के लिए जाना था, तो फिर मैं वहां से निकल गया। कलेक्टर ने कहा कई बार ऐसा होता है कि जो बाकी लोगों के साथ सेवारत और सेवानिवृत शासकीय कर्मचारियों की बातें सुन नहीं पाते और वो लोग हमारे लिए रात दिन काम करते हैं। हमें ऐसा लगा था की इन लोगों को भी सुनना चाहिए, तो जब सामान्य जनसुनवाई 04 बजे खत्म हो जाएगी, जो की लगभग 04 से 04:30 के बीच में खत्म हो जाती है, उसके बाद हमने इन लोगों के लिए समय दिया है, कि जितने लोग आते है, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वो सेवा में हो ऐसे कर्मचारी, किसी भी विभाग के हो, वे आ सकते है और अपनी बात रख सकते है, तो कोशिश करेंगे की उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सकें। जनसुनवाई के दौरान 11 आधार कार्ड, 25 आयुष्मान कार्ड, 23 पीएम किसान सम्मान निधि, एवं 277 व्यक्तियों की स्वास्थ्य जाँच की गई।

परामर्श दात्री समिति की बैठक में जो निर्णय लिये गये थे उसमें से लगभग 70-80 प्रतिशत निर्णयों का पालन हो चुका है-कलेक्टर

जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में अधिकारियों को दिये गये दिशा निर्देश

धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ दमोह, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में आज जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर एसडीएम तेन्दूखेड़ा अविनाश रावत एवं डिप्टी कलेक्टर ब्रजेश सिंह सहित विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारीगण और अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर कोचर ने कहा शासकीय कर्मचारी संगठन है, वह लोग शासकीय कर्मचारियों व अधिकारियों के हितों के लिए लगातार काम करते रहते है और जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार विभागीय परामर्श दात्री समिति की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, तो हमने यह परंपरा निर्मित करने का प्रयास किया है कि रेगुलरली हर तीन महीने में हमारे यहाँ बैठक हो जाए। इसी सिलसिले में आज बैठक का आयोजन किया गया है। कलेक्टर कोचर ने कहा पिछली परामर्श दात्री समिति की बैठक में जो निर्णय लिए थे उसमें से लगभग 70-80 प्रतिशत निर्णयों का पालन हो चुका है और इस बैठक में भी कई बड़े अच्छे सुझाव कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने कहा उनमें से कई का तो हमने मौके पर निराकरण करने की कोशिश की है और बाकी सभी के लिए सभी अधिकारियों को टाइम लाइन दे दी गई है। सब कार्यालय प्रमुखों को आज निर्देश दिये गये है कि आज ही तारीख बताइए की कितनी तारीख को आप अपनी परामर्श दात्री समिति की बैठक कर रहे हो, तो सभी ने आज से लेकर 11 दिसम्बर के बीच में करीब-करीब 10 से 11 विभागों की परामर्श दात्री समिति की बैठक हो जाएगी। यह सभी संगठनों को भी नोट करा दिया है, इससे कई सारे मुद्दे वह लोग स्थानीय स्तर पर सुलझा लेंगे। कलेक्टर ने कहा कई सारे अच्छे सुझाव इस बैठक में प्राप्त हुए हैं, उन सब का हम परिपालन सुनिश्चित कराएँगे। इस दौरान शिकायतें भी प्राप्त हुई है, उन शिकायतों की जांच के निर्देश दिए है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और हम आगे भी नियमित रूप से बैठक करके कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे। जनसुनवाई में भी यह किया गया है कि शाम को 4:30 बजे से, ताकि स्कूल शिक्षक भी उसमें आ सके, शाम 4:30 बजे से सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर्स के लिए जनसुनवाई रखी गई है, जितने सरकारी अधिकारी-कर्मचारी और पेंशनर्स है वह आकर के अपनी व्यक्तिगत शिकायतें बता सकते हैं और हम उनके निराकरण का हर संभव प्रयास करेंगे। इसके साथ ही, इसी महीने पेंशनर एसोसिएशन के साथ एक अलग बैठक करने जा रहे है, ताकि जितने पेंशनर्स है, उनकी समस्याओं के बारे में भी पता चल सके और उसका भी निराकरण हो सके।

ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम कर 70 प्लस बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड का वितरण कराएं-कलेक्टर

कलेक्टर ने ग्रामों का भ्रमण कर विभिन्न कार्यों का किया निरीक्षण

शाजापुर। ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम कर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के बन रहे आयुष्मान कार्ड की प्रिंट का वितरण कराएं। उक्त निर्देश कलेक्टर ऋजु बाफना ने बुधवार को ग्राम टुकराना, छतगांव, कुकड़ी, अभयपुर, सुनेरा एवं मझानिया का भ्रमण कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के निरीक्षण के दौरान दिए। 70 प्लस आयु के बुजुर्गों के बन रहे आयुष्मान कार्ड की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कार्य शीघ्र संपन्न करने और 70 प्लस बुजुर्गों के बने हुए आयुष्मान कार्ड की प्रिंट का वितरण ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित कर करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी शिविर लगाने के लिए कलेक्टर ने कहा। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि उपचार के लिए अनुबंधित अस्पतालों की सूची भी आयुष्मान कार्ड की प्रिंट के पीछे अंकित कराएं। कलेक्टर ने राजस्व महा अभियान 3.0 के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन का निराकरण एवं नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना का सैचुरेशन, आधार लिंकिंग, परम्परागत रास्तों का चिन्हांकन फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियां लक्ष्यानुसार संपादित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने

इस दौरान ग्रामों में अधिक से अधिक खेत तालाब बनाने के लिए सरपंचों से कहा। साथ ही कलेक्टर ने उपयंत्रियों को निर्देश दिए कि शासकीय भूमि पर तालाब बनाने के लिए साईट सिलेक्शन करें। कलेक्टर ने ग्राम अभयपुर एवं सुनेरा में स्टॉप डेम एवं बोरी बंधान का भी निरीक्षण किया। इन ग्रामों में कलेक्टर ने आमजन से उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा। साथ ही उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी भी ली।

एफएलएन गतिविधियों का निरीक्षण- ग्राम सुनेरा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 01 से 03 के विद्यार्थियों में गुणात्मक शैक्षणिक सुधार के लिए चल रही एफएलएन गतिविधियों का निरीक्षण कलेक्टर ने किया। कलेक्टर ने शिक्षिका को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों में शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाएं। कलेक्टर ने यहां अध्ययन कर रहे छात्र आकाश, सुमित, अरसलान, शोएब से किताबें पढ़वाईं एवं जोड़-घटाव कराया। कलेक्टर ने सरपंच सुखराम धाकड़ से कहा कि वे बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए उनके माता-पिता को प्रेरित करें।

टुकराना के किताब घर जंक्शन का निरीक्षण- टुकराना में युवाओं एवं छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बनाए गए किताब घर जंक्शन का निरीक्षण कलेक्टर ने किया। इस दौरान उन्होने किताब घर जंक्शन में उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि वे भी यहां आकर पुस्तकें पढ़ सकते हैं। किताब घर जंक्शन में आवश्यकता अनुसार ओर भी पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन के उपार्जन का निरीक्षण- कलेक्टर ने ग्राम टुकराना एवं सुनेरा के वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर किए जा रहे सोयाबीन उपार्जन के कार्य का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि एफएक्यू मापदण्ड अनुसार ही सोयाबीन की खरीदी करें। इस मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच टुकराना बलदेव सौराष्ट्रीय, छतगांव गोपालसिंह, कुकड़ी सुनील सौराष्ट्रीय, अपने-अपने ग्रामों में उपस्थित थे।

राजस्व महाभियान 3.0 में आ रही समस्याओं एवं मांगों को लेकर पटवारी संघ ने सौंपा ज्ञापन

भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ शाजापुर, राजस्व महाभियान में पटवारियों को आ रही समस्याओं के समाधान एवं अन्य मांगों को लेकर पटवारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार शाजापुर को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिलाध्यक्ष हरिओम हनोतिया के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि लंबित नक्शा तरमीम बटांकन कार्य प्रदेश के पटवारियों से शासन-प्रशासन के द्वारा डंडे के बल पर राजस्व महाभियान के रूप में करवाया जा रहा है, जबकि यह न्यायालयीन प्रकृति का कार्य होकर जिसमें हितबद्ध पक्षकारों सहखातेदारों को संबंधित तहसील न्यायालय के द्वारा सुना जाना आवश्यक होता है। राजस्व महाभियान में नक्शा तरमीम का कार्य वृहद स्तर पर पूर्ण किया जा चुका है, शेष बचे बटांकन नक्शा तरमीम विवादित प्रकृति की होने से उन्हे सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा सुना जानाआवश्यक है। नक्शा तरमीम के कार्य में पटवारी द्वारा प्रस्तावित नक्शा तरमीम को राजस्व निरीक्षक को मौके पर जाकर जांच की जाती है जिसमें समय लगता है, पक्षकारों को सुनवाई करनी होती है। अनुभाग शुजालपुर तहसील शुजालपुर, कालापीपल, अं. बड़ोदिया, पोलायकलां के लगभग 95 प्रतिशत गांवों का एवं जिले में अन्य बहुत सारे ग्रामों का बंदोबस्त नही हुआ है, वर्ष 1925 में बंदोबस्त हुआ था जिसकों लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं, मप्र भू-राजस्व संहिता के अनुसार बंदोबस्त की अवधि 30 वर्ष की रहती है, 30 वर्ष बाद पुन- बंदोबस्त किया जाना चाहिए, परंतु शासन द्वारा एक भी बंदोबस्त नही कराया जबकि इस अवधि में लगभग तीन बंदोबस्त होना था बंदोबस्त नही होने के कारण नक्षा और मौके की स्थिति में काफी भिन्नता हो गई है बंदोबस्त कराया जाए, अनुभाग शुजालपुर के अधिकतर ग्रामों का वर्ष 1982-83 में चकबंदी हुई थी, चकबंदी में अभिलेख तो चकबंदी अनुसार बना दिए परंतु मौके पर उसके अनुसार कब्जा परिवर्तित नही हुआ जिस कारण मौका अभिलेख आपस में मेल नही होता है। मौके पर कोई और भूमिस्वामी बैठा है तथा अभिलेख में किसी और भूमिस्वामी का नाम दर्ज है इसमें सुधार किया जाए, शामिल खसरा की व्यापक समस्या है, बहुत सारे खसरा नंबरों को शामिल कर रकबा संयुक्त दर्ज किया गया है, खसरे में रकबा पृथक-पृथक दर्ज नही होने से रकबा पृथक किया जाना संभव नही है, पूर्व अभियान में जिन नंबरों का रकबा पृथक-पृथक दर्ज था उन्हे पृथक किया जा चुका है, अत- शासन नक्शा तरमीम के कार्य को राजस्व महाभियान के रूप में नही करवाए, इस कार्य को अभियान से पूर्णत- मुक्त रखा जाए, ईकेवायसी फार्मर रजिस्ट्री में शासन द्वारा बनाए गए एप्प पोर्टल को इतना अधिक जटिल बनाया गया है कि किसी भी किसान के नाम में अल्पत्रुटि होने पर भी ईकेवायसी एवं फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, जिससे किसान अनावश्यक उक्त स्थानों पर भटक कर परेशान होता है। उक्त कार्य की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, प्रदेश के पटवारियों पर अधिकारियों द्वारा अनावश्यक दबाव न बनाया जाए, साथ ही अलग-अलग प्रकार के पोर्टल को समाप्त कर एक ही पोर्टल पर सभी योजनाओं की ईकेवायसी करवाई जाने की व्यवस्था की जाए, पटवारियों की समस्याओं एवं मांगों के निराकरण के संबंध में शासन द्वारा पटवारियों को मोबाईल एवं लैपटाप क्रय करने हेतु बजट उपलब्ध करवाया जाए, तहसील कार्यालय में 5जी नेट कनेक्टीविटी उपलब्ध करवाई जाए, शासन के विभिन्न सॉफ्टवेयरों एवं एप्प में आ रही तकनीकी त्रुटियों को दूर किया जाए ताकि पटवारी द्वारा सुविधापूर्वक अभियान का कार्य पूर्ण किया जा सके, पूर्व में संचालित राजस्व महाभियानों में केवल और केवल पटवारियों द्वारा कार्य किया जाता रहा है, जबकि शेष समस्त अधिकारी दिन में तीन से चार बार एक ही कार्य की समीक्षा कर पटवारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं एवं दण्डात्मक कार्रवाई करते हैं। ज्ञापन में समस्या समाधान की मांग की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि पटवारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई तो अभियान का बहिष्कार किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में पटवारी उपस्थित थे।

यूनिसेफ़ जिला समन्वयक अमित शर्मा ने कहा

यदि समय से बच्चें का टीकाकरण कर दिया जाए तो 12 जानलेवा बीमारियों से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है

गौरव सिंघल । सिटी चीफ देवबंद (सहारनपुर)। मदरसा दारुल उलूम देवबन्द में डॉक्टर मतलब अहमद की अध्यक्षता में सीएमओ की उपस्थिति में मदरसा टीचर्स की एक मीटिंग का आयोजन नियमित टीकाकरण, मीजल्स रूबेला कैंपेन एवं पोलियो प्रोगाम के संबंध में किया गया। जिसमें यूनिसेफ़ के जिला समन्वयक अमित शर्मा द्वारा बताया गया कि यदि समय से बच्चे का टीकाकरण कर दिया जाए तो 12 जानलेवा बीमारियों से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ पूजा शर्मा द्वारा नियमित टीकाकरण के बारे में अहम जानकारी प्रदान की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रवीण कुमार द्वारा सवालों को सुनकर उनके जवाब दिए गए और बढ़- चढ़कर टीकाकरण कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए धर्म गुरुओं से अपील की गई। सीएमओ द्वारा बताया गया गया कि टीकाकरण बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाव करने का आसान तरीका है। सीएमओ सहारनपुर द्वारा बताया गया कि 25 से 6 दिसंबर 2024 तक इमेज रूबेला केचप कैंपेन देवबंद, सढ़ोली कदिम और सहारनपुर सिटी ब्लॉक में चलाया जयेगा। जिसमें मीजल्स और रूबेला के टीको के से छूटे बच्चों को ये टीके लगाये जाएंगे साथ ही 8 दिसंबर 2024 से पोलियो बूथ किया जाएगा। जिसमें जीरो से लेकर 5 साल तक ऐसे भी बच्चों को पोलियों की खुराक पिलाई जाएगी। सीएमओ सहारनपुर द्वारा सभी धर्म गुरुओं से बढ़-चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने और अवाम को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए धर्मगुरुओं से अपील की गई। इस अवसर पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी पूजा शर्मा, जिला समन्वयक यूनिसेफ अमित शर्मा, बीएमसी ममता कुमारी, पेसगार रिहान काशमी, डॉ ओबेदुल्ला एवं मदरसा टीचर्स उपस्थिति रहे।

व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता से करें निस्तारण :- डीएम मनीष बंसल

व्यापार बंधु की बैठक हुई आयोजित

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिलाधिकारी सहारनपुर मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला व्यापार बंधु की बैठक आयोजित की गयी। इस अवसर पर उन्होने व्यापार बंधुओं द्वारा उठायी जाने वाली समस्याओं से अवगत होने के बाद उसके गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने ट्रांसपोर्ट नगर में साफ-सफाई के दृष्टिगत 15 दिसम्बर से डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मण्डी समिति रोड़ पर फल व सब्जी की रेहडी वालों को चिन्हित वेण्डिंग जोन पर रेहडी लगवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए नगर निगम अभियान चलाकार अतिक्रमण हटाएं एवं लोकल पुलिस थाना सुनिश्चित करे कि दोबारा वहां पर अतिक्रमण न हो। डीएम मनीष बंसल ने बडतला यादगार जैन मंदिर के पास जलभराव की समस्या के लिए नगर निगम के चीफ इंजीनियर को निर्देशित किया स्थलीय भ्रमण कर समस्या का स्थाई समाधान कराना सुनिश्चित करें। बेहट रोड़ पर टूटे डिवाईडर की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करे। क्लार्क होटल चौराहे से सिविल हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली सड़क पर खराब पडी स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक, संयुक्त आयुक्त राज्यकर अमित पाठक, उपायुक्त प्रशासन राज्यकर एपी सिंह, हरपाल सिंह वर्मा, नुसरत साबरी, अजय शर्मा सहित अन्य व्यापारी बंधु तथा संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आजीविका अमरकंटक कोदो प्रसंस्करण इकाई से आजीविका मिशन के दीदियों को 2.92 लाख रुपये का हुआ शुद्ध आय

सुशिल सोनी । सिटी चीफ अनूपपुर, स्व सहायता समूह की क्रांति महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का आधार बन गई है। शासन एवं प्रशासन की मदद से महिलाएं खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सफलता के नित नए आयाम छू रही हैं। इसी कड़ी में अनूपपुर जिले के जनजातीय बाहुल्य विकासखंड पुष्पराजगढ़ के ग्राम कोहका पूर्व में जिला प्रशासन के सहयोग से आजीविका अमरकंटक कोदो प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई। इसके संचालन की जिम्मेदारी म.प्र. डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जीवनदायिनी संकुल संगठन किरगी को दी गई। जिले में किसानों द्वारा किए जा रहे कोदो उत्पादन को बेहतर बाजार एवं उचित मूल्य प्रदान करने एवं स्व सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कोदो प्रसंस्करण इकाई का संचालन प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि कोदो को ''एक जिला एक उत्पाद'' अंतर्गत भी चिन्हित किया गया है। जीवनदायिनी संकुल संगठन किरगी द्वारा आजीविका अमरकंटक कोदो इकाई का संचालन संकुल अंतर्गत ग्रामों के तीन स्व सहायता समूहो के 12 सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ अप्रैल 2023 को किया गया था। इस इकाई द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से कोदो को बेहतर पैकेजिंग के साथ बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में जिले के स्थानीय बाजारों एवं पड़ोसी जिला शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी के बाजारों में कोदो उत्पाद के विक्रय हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया गया जिसमें बिक्री में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में आजीविका अमरकंटक कोदो प्रोसेसिंग इकाई के द्वारा प्रतिदिन औसतन 400 पैकेट (200 किलोग्राम) कोदो का प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कार्य किया जाता है। जिसमें लागत 80 रुपये प्रति किलोग्राम आती है। अब तक इकाई द्वारा 195 क्विंटल कोदो का प्रसंस्करण कर विक्रय किया जा चुका है, जिससे संकुल संगठन को लगभग 2.92 लाख रुपये का शुद्ध आय प्राप्त हुआ है। कोदो विक्रय को बढ़ावा देने के लिए कोदो प्रसंस्करण के साथ-साथ इसी इकाई में कोदो कुकीज बनाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिसमें अब तक कुल 157 क्विंटल कोदो कुकीज का विक्रय किया जा चुका है। जिससे जीवनदायिनी संकुल संगठन किरगी के स्व सहायता समूह की दीदियों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है। स्व सहायता समूह की दीदियों का कहना है कि आजीविका अमरकंटक कोदो प्रसंस्करण इकाई से हमारा आर्थिक एवं सामाजिक स्तर सुधरा है तथा इससे हमें 2.92 लाख रुपये का शुद्ध आय प्राप्त हुआ है। इस हेतु हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता से करें निस्तारण : डीएम मनीष बंसल

औद्योगिक क्षेत्र पिलखनी में भूखण्डों के सत्यापन के लिए एसडीएम, सदर की अध्यक्षता में कमेटी गठित

गौरव सिंघल । सिटी चीफ सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला उद्योग बंधु की बैठक आयोजित की गई। जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि निर्धारित समयसीमा में उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि उद्योगबंधुओं से जुडे कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करें। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा के उपरान्त लम्बित प्रकरणों को निस्तारण किये जाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिये। उन्होने जिला पंचायत से संबंधित प्रकरणों को बोर्ड बैठक में प्रस्तुत कर प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर स्वीकृत कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र, पिलखनी में रिक्त भूखण्डों एवं बन्द पडी इकाईयों के संयुक्त सत्यापन के लिए एसडीएम, सदर की अध्यक्षता में कमेटी गठित करते हुए आरएम, यूपीसीडा, मेरठ को अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये। दिल्ली रोड फोरलेन बाईपास तक के क्षेत्र को थाना सदर बाजार के अन्तर्गत किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया है। एसपी, यातायात को दिल्ली रोड पर आयुक्त कार्यालय से लेकर औद्योगिक आस्थान क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाये जाने के लिए प्रतिदिन कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, एस पी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, डीसी डीआईसी वीके कौशल, आईआईए से अनूप खन्ना, लघु उद्योग भारती से अनुपम गुप्ता व सीएसआई से अध्यक्ष रविन्द्र मिगलानी, मनजीत अरोडा, अध्यक्ष-हौजरी एसोसिएशन, संजीव शर्मा-अध्यक्ष, आईआईबीए एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

धुंधलका मंडल के शक्ति केंद्र डिगावमाली के बुथ पर चुनाव सम्पन्न

पिपलियामंडी- संगठन पर्व के तहत भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नानालाल अटोलिया के निर्देशानुसार मल्हारगढ़ विधानसभा के धुंधडका मंडल के शक्ति केंद्र डिगांव माली के बूथ 199, 200 पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की जिसमें नवीन बूथ अध्यक्ष/समिति का चयन सर्व सम्मति से किया गया, साथ ही नवीन बूथ समिति का संगठन ऐप पर डाटा एंट्री पूर्ण की । बुथ निर्वाचन प्रभारी पिपलियामंडी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील देवरिया ने सभी नवीन पदाधिकारीयो को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सोशल मीडिया विधानसभा प्रभारी इंद्रजीत भट्ट, जिला भाजपा कार्यालय सहमंत्री कन्हैयालाल शर्मा, शक्ति केंद्र प्रभारी श्री भागीरथ विश्वकर्मा ,शक्ति केंद्र संयोजक श्री राम शर्मा, सहसंयोजक बालाराम नागर, मंडल सोशल मीडिया राहुल टेलर , जनपद सदस्य जय सिंह चौहान, नवीन बूथ अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, जसवन्त आंजना, भवरलाल आंजना, गंगाराम मीणा, अरुण बैरागी, दसरथ डेल, आदि बूथ निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपस्थित रहे!

पूंजीपति लोग सत्ताधारियों से मिलकर गरीब व दलित, आदिवासियों, वंचितो की आवाज दबाने का काम करते है। दत्तू मेढे... नहीं सुनने पर झूठे मुकदमे बनते है।

बुरहानपुर,पिछले कई समय से टावर का विरोध चल रहा है इसी के चलते हुए ग्राम मोहम्मदपुर के समस्त निवासी आज कलेक्टर के पास में पूरा गांव उठकर जाने के बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब न्यायालय के शरण में जाने के लिए तैयार है। मोहम्मदपुर वासी ।आज सारी महिलाएं अपना काम धंधा छोड़कर न्याय के लिए मान्य कलेक्टर महोदय के पास पहुंची थी परंतु उन्हें संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण वह नाराज हो गई है इसी के चलते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा एक इंजीनियर भेज कर टावर का निरीक्षण किया गया गांव वालों के सामने उसके बाद रिपोर्ट बनाकर मान्य कलेक्टर महोदय को सौंप दी गई है ।सत्ताधारी और पूंजीपति मिलकर गरीबों से खेल खेलने में इन्हें आनंद आता है । टावर गिरने का भाई ग्रामीणों में बना हुआ है क्योंकि इसके पूर्व भी बीएसएनल का टावर जिले में गिर चुका है जिसका परिणाम शासन प्रशासन स्वयं जानती है ।

हत्या के प्रकरण में 16 साल से फरार चल रहे आरोपी को नेपानगर पुलिस ने किया गिरफ्तार

जिला खंडवा के थाना किल्लोद के 16 साल से फरार हत्या के आरोपी रामचंद्र पिता शिवनारायण जाति गौंड उम्र 47 साल निवासी ग्राम भवरदी थाना छीपावड जिला हरदा को नेपानगर पुलिस ने किया गिरफ्तार द्वारा

बुरहानपुर, (नेपानगर)घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 18-11-2024 को आवेदिका हेमलता पति विप्पल धुर्वे 35 वर्ष निवासी ग्राम बीड ने अनावेदक सुरेश पिता नामालुम ग्राम बीड उम्र के विरूद्ध लडाई झगडा का एक लिखित आवेदन पत्र दिया था। आवेदन पर कार्यवाही हेतु अनावेदक सुरेश को तलब करने हेतु थाना नेपानगर से डायल 100 को भेजा गया था परंतु रात्रि में कही फरार हो गया था जिसे दूसरे दिन दिनांक 19-11-2024 को पुनः डायल 100 को रवाना कर अनावेदक सुरेश को पकड़ने हेतु भेजा गया जिसे डायल 100 द्वारा लाया गया एवं आवेदिका हेमलता को भी बुलाया गया जिसके द्वारा बताया गया कि अनावेदक सुरेश इसके द्वारा पूर्व में मडर करने की बात बोलकर मुझे भी मारने की धमकी दे रहा है। जिससे थाना प्रभारी निरी0 ज्ञानु जायसवाल द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुये अनावेदक सुरेश पिता संतोष जाति गाँउ उम्र 47 साल निवासी ग्राम बीड से बारीकी से पूछताछ की जिसके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2008 में ग्राम जुनापानी एवं भवरदी में निवास कर खेती मजदूरी का काम कर रहा था। जहां विवाद के चलते मैंने हरदा के विश्नोई की हत्या कर दी थी और उसकी मोटर सायकल लेकर में बैतुल, आकोल के रास्ते से भागकर एवं अपना नाम बदलकर व आधार कार्ड नया बनाकर ग्राम बीड थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर में रह रहा हूँ। पूछताछ के दौराने आरोपी ने अपना नाम कभी सुरेश पिता संतोष बताया तो कभी चंदर पिता शिवनारायण, तो कभी रामचंद्र बताया। उक्त मामले को संज्ञान में लेते हुये थाना प्रभारी निरी0 ज्ञानु जायसवाल, उनि कलीराम मौर्य, सउनि सुनिल दुबे, सउनि जगदीश मंसूरे, आर. 79 सुरेश गोयल द्वारा थाना हरदा, खंडवा के थानों से हत्या के प्रकरण में फरार आरोपी सुरेश पिता संतोष जाति गौड की जानकारी लेते हुये मामला थाना किल् लोद जिला खंडवा को होना पाया गया जहां अपराध क्रमांक 26/2008 धारा 302, 201 भादवि में 16 वर्षों से फरारी स्थाई वांरटी होना बताया गया। थाना प्रभारी किल्लोद को अवगत कराते हुये किल्लोद पुलिस को बुलाया गया जिन्होंने रामचंद्र पिता शिवनारायण जाति गोंड उम्र 47 साल निवासी भवरदी थाना छीपावड जिला हरदा एवं बदला हुआ नाम सुरेश पिता संतोष जाति गौंड उम्र 47 साल निवासी ग्राम बीड थाना नेपानगर को गिरफ्तार कर अपनी मूल इकाई लेकर अपने 16 वर्षों से पुराने फरारी स्थाई वारंटी की तामील न्यायालय में पेश की गई। महत्वपूर्ण भूमिका निरी0 ज्ञानु जायसवाल उनि कलीराम मोर्य, सउनि सुनिल दुबे, सउनि जगदीश मंसूरे,आर0 79 सुरेश गोयल,आर0 556 दुर्गेश पटेल,आर0 548 सत्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

दो दिन से धरने पर बैठा परिवार

किसका दोष कौन जिम्मेदार ? कलेक्टर तक शिकायत के बाद भी कोई असर नहीं

जावरा– रतलाम ज़िले में स्थित जावरा नगर पालिका परिषद सीएमओ कार्यालय के बाहर एक परिवार सोमवार धरने पर बैठ गया।शिकायत सुनने सीएमओ दुर्गा बामनिया आई तो तत्काल निराकरण की बात पर अड़ गए ऐसे में सीएमओ बामनिया शिकायत सुन परिषद के कार्यों से जुड़ी मीटिंग में व्यस्त हो गईं। लगभग 2 घंटे बीतने के बाद भी धूप में बैठा परिवार टस से मस नहीं हुआ। फिर स्थ्रू के कहने पर तहसीलदार द्वारा मामला संज्ञान में लिया गया और आश्वासन पर मामला शांत हुआ और मंगलवार सुबह तहसीलदार, पटवारी ओर नगर पालिका परिषद की आधिकारिक टीम शिकायत पर मंथन करने वार्ड नंबर एक के वाद विवाद परिदृश्य को समझने पहुंची। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता भेरूलाल पोरवाल का कहना हैं कि जावरा वार्ड नंबर एक के भाजपा पार्षद के परिवार जनों द्वारा अवैध रूप से घर के पास वाली गली के साथ उनके मकान के बाहर तक अतिक्रमण कर लिया है,अतिक्रमण के चलते फरियादी के घर का रास्ता भी बंद हो गया हैं। वे पिछले 6 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं शिकायत के चलते अतिक्रमण धारी मूलचंद पिता नंदाजी गेहलोत के परिवार जनों ने शिकायतकर्ता भेरूलाल पोरवाल की पत्नी व बच्चियों के साथ मारपीट की, मारपीट के बाद मामला रविवार के दिन सिटी थाने पहुंच गया, प्रताड़ना से परेशान होकर भैरूलाल पिता मांगीलाल पोरवाल स्वयं अपनी पत्नी, व दो बच्चियों के साथ अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जावरा नगर पालिका परिषद् में सोमवार को धरने पर बैठे रहे। सुनवाई नहीं होने पर शिकायतकर्ता मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय धरना देने पहुंचे। शिकायतकर्ता की पत्नी प्रियंका पोरवाल द्वारा पूर्व में सूचना अधिकार में मूलचंद पिता नंदाजी गेहलोत के भवन निर्माण कि उक्त भूमि की 1980 से वर्तमान तक का रिकॉर्ड मांगा गया था जो कि नगर पालिका परिषद के द्वारा मूलचंद पिता नंदाजी गेहलोत से मांगा भी गया था लेकिन 1980 से वर्तमान तक के रिकॉर्ड को लेकर उन्होंने व्यक्तिगत जानकारी का उल्लेख कर जानकारी देने से ना कर दिया जिस बाबत निकाय द्वारा पत्र क्रमांक 258 के अनुसार 19/4/2022 से सूचना के संबंध में जानकारी सौंपी गई। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा विषय की गंभीरता पर जांच के बाद मीडिया द्वारा जवाब मांगने पर बताया की नगर पालिका परिषद के राजस्व रिकॉर्ड में नगर पालिका परिषद की सर्वे रिपोर्ट में गली नहीं हैं। यह सर्वे 2001 में किया गया था वहीं स्थानीय निवासी से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा की यहां शासकीय गली थी। चुकीं तहसीलदार संदीप इवने का कहना हैं कि मौखिक आधार पर गली बताना मान्य नहीं होगा हमें लिखित दस्तावेज चाहिए वहीं इस ओर दस्तावेज का आधार माने तो पूर्व में बस्ती क्षेत्र होने से 1975 से पहले का सीमांकन भूमि नक्शा रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है ऐसे में सिर्फ़ नगर पालिका परिषद द्वारा रहवासी क्षेत्र के आधार पर भूमि स्वामी के नक्शे को मान्य कर उसे सही ठहराना कहा का तर्क सही है। आखिर शासन की चल अचल संपत्ति में राजस्व की भूमि रिकॉर्ड में कहा ग़लती हुई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

भिक्षावृति रोकथाम हेतु अभियान

बुरहानपुर–जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले भिक्षावृत्ति में लगे हुए बच्चों की पहचान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। सर्वे दलों द्वारा भ्रमण करते हुए जन–जागरूकता लायी जा रही है। बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सर्वे दलों का गठन किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सुषमा भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 76 के तहत बालक का भिक्षा के लिये प्रयोग करने पर या बच्चें से भिक्षावृत्ति कराने पर 5 वर्ष का कारावास व एक लाख रूपये के दंड का प्रावधान है।

घर-घर दस्तक हर पात्र हितग्राही के तैयार किये जा रहे है, आयुष्मान कार्ड

बुरहानपुर–चाहे स्कूली विद्यार्थी हो, चाहे 70 प्लस या निर्माण श्रमिक के साथ ही हर एक पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने का प्रयास जारी है। जिला प्रशासन की मंशा है कि, कोई भी पात्र हितग्राही आयुष्मान भारत निरामय योजना से वंचित ना रहे। सभी के आयुष्मान कार्ड बनाये जाये, ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रूपये तक का निःशुल्क उपचार मिल सकें।

जिले में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के मार्गदर्शन में शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। अधिकारियों द्वारा सेक्टरवार बैठक लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने के दौरान आने वाली समस्याओं का भी निदान करवाया जा रहा है। अमले को आसान प्रक्रिया के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया गया है। यह भी निर्देश दिये गये है कि, नागरिकों में आयुष्मान योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। अब 70 प्लस या उससे अधिक आयु वर्ग के हितग्राही भी आयुष्मान योजना के पात्र है। इस हेतु हितग्राहियों के घर–घर जाकर प्रशासन दस्तक दे रहा है। हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ–साथ योजना के फायदे भी बतलाये जा रहे है। शालाओं में विद्यार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है। दूर–दराज ईलाकों में भी आयुष्मान टीम पहुँचकर कार्य कर रही है।

70 वर्ष अथवा अधिक आयु के वृद्धजन स्वयं अथवा अपने परिजन की मदद से आयुष्मान एप के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं

धार / 70 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले वृद्धजन अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं अथवा अपने परिजन की मदद से आयुष्मान एप के माध्यम से बना सकते हैं। आयुष्मान एप पे फेस ऑथेंटिकेशन से कार्ड बन सकता है।कोई भी व्यक्ति इस एक एप से कई 70 वर्ष और अधिक की आयु वाले लोगों का कार्ड बना सकता है। समग्र ई केवाईसी की आवश्यकता आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नहीं है।अगर हितग्राही 70 प्लस हो तो समग्र आईडी की आवश्यकता नहीं है।ये जानकारी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में 70 वर्ष से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने और राजस्व महा अभियान 3.0 के संबंध में आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में ज़िला पंचायत के सीईओ अभिषेक चौधरी सहित समस्त एसडीएम और सीएमओ मौजूद रहे।कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पटवारी नियमित रूप से रोस्टर अनुरूप अगर कैम्प पे नहीं जा रहे हैं तो निलंबन की कार्यवाही की जाए।लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत दिए आवेदनों के निराकरण समय सीमा के बाहर होने पर पेनाल्टी लगाएँ।कहा अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करें और निकम्मों को दंडित करे।राजस्व अधिकारी गण परंपरा गत रास्ते के मामले में ग्रामसभा से वेरीफाई कराएँ और स्वयं मौक़ा निरीक्षण करें। खसरे में आधार की लिंकिंग का कार्य कराएँ। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि आधार कार्ड बनाने, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र तथा समग्र आई डी बनाए जाने के लिए विशेष प्रयास मैदानी स्तर पर किये जाए तथा प्रतिदिन की प्रगति को मॉनीटर किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आईसीडीएस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व सहित अन्य विभागीय अमले को इस अभियान में लगाते हुए प्रतिदिन प्रगति सुनिश्चित करायी जाये।उन्होंने निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी केन्द्रों संबंधी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित कराया जाए। समय सीमा में बाहर प्रकरणों के अंतर्गत कोताही बरतने वाले संबंधित व्यक्ति पर दंड की कार्रवाई की जाए। बैठक में उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मैदानी स्तर पर जागरूकता के लिए विशेष आईईसी गतिविधियों के संबंध में निर्देश दिए।कलेक्टर ने राजस्व अभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा करते हुए मैदानी स्तर पर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व अभियान अंतर्गत नामांतरण, बंटवारे, नक्शा बटांकन, अभिलेख दुरस्ती, सीमांकन, पीएम किसान योजना अंतर्गत ईकेव्हायसी एवं आधार से जोडने के कार्य सहित अन्य कार्यों की प्रगति के संबंध में निर्देश दिए।

अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस पर आयोजित व्याख्यान

उज्जैन। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर राजनीति विज्ञान और लोकप्रशासन मानवाधिकार आयोजित व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ.अजय सिंह भदौरिया ने बाल अधिकार के कानूनों के साथ मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से बच्चों के लिए चल रही योजनाओं को बताया, साथ ही समाज के कर्तव्य को बताते हुए सभी स्टूडेंट्स से बच्चों की हेल्प के लिए हमेशा कर्तव्य निष्ट रहने और देश में कोई बच्चा भूखा न रहे, ऐसे मन से काम करने का आह्वान किया। दूसरे वक्ता जितेंद्र शर्मा ने बाल अधिकार बताए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ.नलिन सिंह पवार ने की, आभार डॉ वीरेंद चावरे ने माना। कार्यक्रम में डॉ.शिव कुशवाह, डॉ.उमा शर्मा, डॉ.ज्योति चौहान और स्टूडेंट्स उपस्थित रहे।

मोटरसाइकिल को बचाने मे पलती तूफान,आठ हुए घायल

काकड़िया फाटे पर हुआ हादसा

.....भग्यापुर व भगवानपुरा के बिच में बुधवार शाम पांच से बजे के करीब काकड़िया फाटे के पास बाईक सवार को बचाने में एक तूफान गाड़ी क्रमांक एमपी 13 ",श्व, 4846 पलटी खा गईं, हादसे में आठ लोगों को चोटें आई हैं, ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस वाहन से भगवानपुरा के शासकीय अस्पताल भेजा गया,जहां पर डॉक्टर शेफाली विश्वास के द्वारा उनका उचित उपचार किया गया,डॉक्टर शेफाली विश्वास ने बताया कि, हादसे में कुल आठ लोग घायल हुए हैं,इनमें से एक बुजुर्ग को सिर में अधिक चोट लगने के कारण उन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, प्राप्त जानकारी अनुसार हादसे में बड़वानी जिले के पलसूद क्षेत्र के ग्राम दौंदवाड़ा निवासी मांगीलाल पिता लौटा 60वर्ष,यशराज पिता राजू 9वर्ष,सुनील पिता अनारसिंह 30वर्ष , गमरिया पिता दादा 62वर्ष, लहंगू बाई पति सुनील 27वर्ष, गुरली बाई पति रमेश 45वर्ष, रूमली बाई पति खेमसिंह 50वर्ष, सहित एक अन्य बालक घायल हुआ हैं, वहीं एक सौ आठ एंबुलेंस वाहन से घटना की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचे,और घायलों को अस्पताल लेकर गए, वाहन में सवार गुरली बाई,और गोलू बर्ड ने बताया कि हम दौंदवाड़ा से बुरहानपुर में रिश्तेदारों के यहां पर पाटले के कार्यक्रम में जा रहे थे,तभी भगवानपुरा के आगे काकड़िया फाटे पर सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने में वाहन अनियंत्रित हो गया ।

वन सुरक्षा श्रमिकों ने वन परिक्षेत्र अधिकारी टिकरिया को ब्याज की राशि एवं नियमित कार्य पर रखने हेतु दिये लिखित आवेदन

मंडला निवास/ मंडला- मंडला के जिले अंतर्गत वन परिक्षेत्र टिकरिया फड़की बीट सिवनी माल के वन सुरक्षा श्रमिकों ने वन विभाग को ब्याज की राशि एवं नियमित कार्य पर रखने हेतु 22/10/2024 को पोस्ट आफिस निवास द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से लिखित आवेदन दिए हैं। लिखित आवेदन के माध्यम से उन्होंने साफ–साफ कहा हम आवेदकगणों की विनम्र पूर्वक निवेदन है कि हमारे द्वारा किए गए वन सुरक्षा श्रमिक के कार्य पर वर्ष 2007 में नियोजित किए गए थे,और हमने अक्टूबर 2011 तक निरंतर कार्य किया है। जिसमें फरवरी 2009 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि में लंबित समय से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जिससे कई बार विभाग के जिम्मेदारों को आवेदन निवेदन किया गया। परंतु भुगतान न किए जाने पर व्यथित होकर माननीय श्रम न्यायालय जबलपुर के समक्ष याचिका क्रमांक 40/पी. डब्ल्यू एक्ट/2014 प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/10/ 2015 को राशि 2.69.280 रू. का भुगतान हेतु आदेशित किया गया था। जिसके बाद भी उक्त आदेश का पालन न किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय मुख्य खंडपीठ जबलपुर में याचिका स्थ्र3561/2023 प्रस्तुत किए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18/07/2023 को आदेशित किया गया। उक्त भुगतान हेतु जिस पर अक्टूबर 2024 में सिर्फ राशि 2.69.280/– रू. का भुगतान किया गया है। जबकि उच्च न्यायालय जबलपुर जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2011 से अक्टूबर 2024 तक की ब्याज 12त्न प्रतिवर्ष के हिसाब से राशि 4 लाख 52,390/–रू. का भुगतान होना था जिसे नहीं किया गया है। अतः माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि ब्याज की राशि 4 लाख 52,390/–रू. का भुगतान अति शीघ्र हम वन सुरक्षा श्रमिकों को किया जाए तथा साथ ही पुनः कार्य में रखते हुए वर्ष 2007 से निरंतर कार्य सेवा मानी जाए, अन्यथा हमें विवश होकर माननीय न्यायालय के शरण में न्याय हेतु जाना पड़ेगा।

आवेदकगण....... 1. संजय चौधरी/पिता उत्तम लाल चौधरी 2. सुवेंद्र कुमार/ पिता बजरू तेकाम 3. सगनी बाई बेवा/पति जगत सिंह मरावी 4. सिंधी सिंह/पिता बुद्धू सिंह कुशराम

जल्द शुरू होने जा रहा एयरपोर्ट टोल टैक्स सिस्टम, चार्ज किया जाएगा इतना पैसा

नेशनल डेस्क. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जल्द ही उन लोगों से टोल टैक्स लिया जाएगा, जो अपने परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों को रिसीव करने के लिए अराइवल टर्मिनल पर आते हैं। दिल्ली एयरोपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (डायल) टी-3 के अराइवल टर्मिनल पर त्नएयरपोर्ट टोल टैक्स वसूलने की योजना बना रही है। यह टोल टैक्स ठीक वैसे ही लिया जाएगा, जैसे टोल रोड पर वाहन मालिकों से टोल लिया जाता है।

क्या होगा नया सिस्टम?

केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, डायल ने इस सिस्टम के लिए पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है और इसके लिए टी-3 के अराइवल टर्मिनल की थर्ड लेन में नया सिस्टम भी लगा दिया गया है। इस व्यवस्था के तहत कारों को एक निश्चित समय तक अराइवल टर्मिनल की थर्ड लेन में खड़ा होने की अनुमति दी जाएगी। पहले आठ से दस मिनट तक यह समय मुफ्त रहेगा, लेकिन इसके बाद यदि कोई वाहन और समय तक खड़ा रहता है तो उसे उस समय का चार्ज वसूला जाएगा।

चार्ज होगी कितनी राशि

सूत्रों के अनुसार, इस एयरपोर्ट टोल टैक्स की शुरुआती दर लगभग 70 रुपए हो सकती है। यह चार्ज फास्टैग के माध्यम से भी वसूला जा सकता है, जैसे टोल रोड पर लिया जाता है।

पहले भी हुआ था एक नया बदलाव

इससे पहले डायल ने टी-3 के अराइवल टर्मिनल पर एक नया सिस्टम लागू किया था, जिसमें प्राइवेट गाड़ियों को सीधे अराइवल टर्मिनल में जाने से रोक दिया गया था। अब उन्हें अनिवार्य रूप से मल्टीलेवल कार पार्किंग में पार्क करने के लिए कहा जाता था। पहले कुछ मिनटों के लिए पार्किंग फ्री थी, लेकिन उसके बाद पार्किंग के लिए चार्ज लिया जाता था।

मार्शल सिस्टम की जगह अब एयरपोर्ट टोल टैक्स सिस्टम

अराइवल टर्मिनल में ट्रैफिक जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए डायल ने पहले मार्शल सिस्टम लागू किया था। इस सिस्टम में मार्शल गाड़ियों को खड़ा होने से रोकते थे, ताकि ट्रैफिक नियंत्रण में रहे। अब डायल मार्शल सिस्टम की जगह नया एयरपोर्ट अराइवल टोल टैक्स सिस्टम लागू कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस नए सिस्टम का ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

ईरान की यूनिवर्सिटी में न्यूड होकर हिजाब का विरोध करने वाली छात्रा पर अदालत ने सुनाया हैरानीजनक फैसला

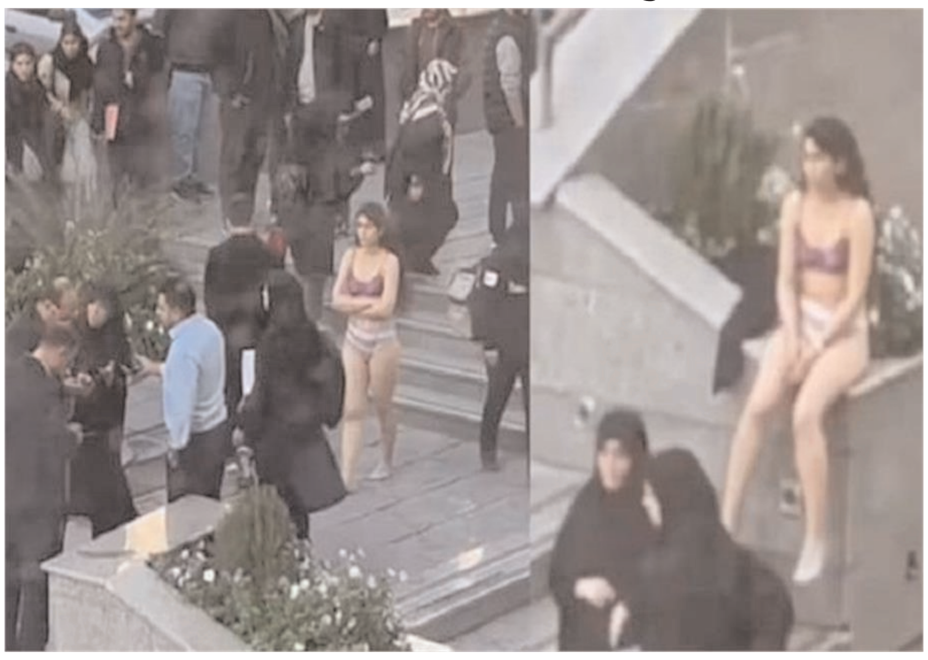

तेहरान. ईरान की राजधानी तेहरान की एक यूनिवर्सिटी में अंडरवियर में घूमने वाली छात्रा का मामला दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गया था। इस घटना के बाद सभी की नजरें अदालत के फैसले पर थीं। अब ईरान की अदालत ने छात्रा को रिहा कर दिया है, और उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। लड़की को मानसिक स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था। डॉक्टरों ने पाया कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया है और उसके खिलाफ कोई न्यायिक मामला नहीं चलेगा। अदालत ने माना कि छात्रा के असामान्य व्यवहार की वजह उसकी पारिवारिक समस्याएं और मानसिक स्थिति थी। उसके साथी और करीबी पहले भी ऐसे लक्षण देख चुके थे।

नवंबर की शुरुआत में वायरल हुए वीडियो में इस छात्रा को तेहरान की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में अंडरवियर में घूमते हुए देखा गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला न केवल ईरान, बल्कि दुनियाभर में सुर्खियों में आ गया। ईरान में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लागू किए गए सख्त ड्रेस कोड के तहत महिलाओं के लिए सिर ढकने वाले कपड़े पहनना अनिवार्य है। इस नियम के तहत पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनने को लेकर छात्रा को कड़ी सजा मिलने की आशंका जताई जा रही थी। घटना के बाद दुनियाभर के मानवाधिकार संगठनों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ईरान से छात्रा को सजा न देने की अपील की और महिलाओं के ड्रेस कोड कानून की आलोचना की।

यूनिवर्सिटी की देखरेख के मंत्री हुसैन सिमोई ने इस घटना को अनैतिक कृत्य करार दिया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रा को यूनिवर्सिटी से निष्कासित नहीं किया गया। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह न तो नैतिक है और न ही धार्मिक रूप से उचित। ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड कानून को देश की मोरल पुलिस लागू करती है। इसके उल्लंघन पर सजा दी जाती है। साल 2022 में महसा अमिनी नामक 22 वर्षीय महिला की ड्रेस कोड के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में मौत के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे।

जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले देशों की सूची में दो पायदान फिसला भारत

नेशनल डेस्क. जलवायु परिवर्तन से निपटने के मामले में प्रगति करने वाले देशों की सूची में भारत पिछले साल के मुकाबले दो पायदान नीचे खिसक गया है। हालांकि, प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तेजी से अपनाने के कारण वह अब भी शीर्ष-10 में बरकरार है। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। थिंक टैंक 'जर्मनवॉच, 'न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और 'क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल की ओर से प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई 2025) में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की नीति के मामले में दुनिया के शीर्ष उत्सर्जक देशों की प्रगति का आकलन किया गया है। सीसीपीआई-2025 में यूरोपीय संघ (ईयू) सहित जिन 63 देशों की जलवायु प्रगति का मूल्यांकन किया गया है, वे 90 फीसदी वैश्विक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत को इस सूची में 10वें पायदान पर रखा गया है। हालांकि, सीसीपीआई-2025 में कहा गया है कि भारत की जलवायु नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें कहा गया है कि उद्योगों के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग और आबादी में वृद्धि के कारण जलवायु कार्रवाई को लेकर विकासोन्मुख दृष्टिकोण जारी रहने या मजबूत होने की गुंजाइश है।

सीसीपीआई-2025 में शीर्ष तीन स्थान खाली रखे गए हैं, क्योंकि किसी भी देश ने सूची के सभी पैमानों पर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसे कुल मिलाकर बहुत उच रेटिंग दी जाए।

अधिकांश E&it Poll में भाजपा की जीत का दावा

झारखंड में इस बार खिल सकता है कमल

रांची- झारखंड के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सामने आए एग्जिट पोल में राय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता में आने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती नजर आ रही है। वहीं, जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है।

मतदान के बाद जारी विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल पर भरोसा करें तो राय में सत्ता परिवर्तन तय है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक, सत्ता की कमान भाजपा के हाथ में जाएगी। भाजपा को सामान्य बहुमत से अधिक सीटें मिल सकती है। विभिन्न एग्जिट पोल में राजग को 40 से लेकर 53 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि झामुमो नीत आईएनडीआईए को 25 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में झामुमो नीत आईएनडीआईए को 53 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की गई है।

पांच एग्जिट पोल के नतीजे

चाणक्या के एग्जिट पोल में राजग को 45-50 और आईएनडीआईए को 35-38 सीटें, मैट्रिज ने राजग को 42-47 और आईएनडीआईए को 25-30 सीटें, पीपुल्स पल्स ने राजग को 44-53 और आईएनडीआईए को 25-37 सीटें, जेवीसी ने राजग को 40-44 और आईएनडीआईए को 30-40 सीटें, एक्सिस माय, इंडिया ने आईएनडीआईए को 53 और राजग को 25 सीटें दी है। वहीं, इस बीच

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, हम एग्जिट पोल से अलग हैं। हम 50-55 सीटें पार करने जा रहे हैं। यह झारखंड के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार होगी। लोग इस सरकार से तंग आ चुके थे। जेएमएम की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीएम 5 महीने जेल गए। जनादेश हमारे पक्ष में हैं।

यह 23 नवंबर को मतगणना शुरू होने पर सच साबित होगा। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी एग्जिट पोल पर अपनी राय रखी है।

गौरतलब है कि साल 2019 के विधानसभा चुनावों में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 47 सीटें और एनडीए को 25 सीटें मिली थी। वोट शेयरिंग की बात करें तो, मैटराइज के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा गठबंधन को 44.9 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है। जबकि, जेएमएम-कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का वोट शेयर 38.2 फीसदी रह सकता है। वहीं, सर्वे में अन्य को 16.9 प्रतिशत वोट शेयर का अनुमान लगाया गया है।

गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल हुए श्री श्री रविशंकर

नेशनल डेस्क. वैश्विक आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी नेता श्री श्री रविशंकर ने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में भाग लिया। इससे पहले मंगलवार को गोवा में कर्टेन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि गोवा फिल्मों के भव्य महोत्सव में प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि आईएफएफआई 2024 को 101 देशों से रिकॉर्ड 1,676 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो महोत्सव की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रमाण है। ढ्ढस्नस्नढ्ढ 2024 में 81 देशों की 180 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्में प्रस्तुत की जाएंगी, जिनमें 16 विश्व प्रीमियर, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 43 एशियाई प्रीमियर और 109 भारतीय प्रीमियर शामिल हैं। वैश्विक सर्किट से प्रतिष्ठित शीर्षकों और पुरस्कार विजेता फिल्मों के चयन के साथ, इस वर्ष का महोत्सव दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार है।

आईएफएफआई परेड के मार्ग पर स्काई लैंटर्न प्रतियोगिता का प्रदर्शन किया जाएगा और प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को ईएसजी कार्यालय स्थल से कला अकादमी तक आईएफएफआई परेड का आयोजन किया जा रहा है। आईएफएफआई 2024 युवा फिल्म निर्माताओं - द फ्यूचर इज़ नाउ पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। ढ्ढस्नस्नढ्ढ 2024 की थीम, यंग फिल्ममेकर्स- द फ्यूचर इज नाउ, विश्व सिनेमा के भविष्य को आकार देने में नई आवाज़ों के महत्व को रेखांकित करती है।

देश भर में युवा फिल्म निर्माण प्रतिभाओं को पहचानने के लिए नया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ भारतीय नवोदित निर्देशक स्थापित किया गया है, जिसे युवा फिल्म निर्माताओं पर केंद्रित आईएफएफआई की थीम के साथ जोड़ा गया है। कुल प्रस्तुत 102 फिल्मों में से 5 फिल्में इस पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। पुरस्कार में प्रमाणपत्र और रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। समापन समारोह में 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली जमानत

इस्लामाबाद. हाईकोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने सुनवाई की अध्यक्षता की और 1-1 मिलियन रुपए के दो जमानती बॉन्ड जमा करने की शर्त पर जमानत मंजूर की।

कोर्ट ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह सहयोग करने का निर्देश दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है।

इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने मई 2021 में सऊदी अरब यात्रा के दौरान वहां के एक शाही सदस्य से मिले बेशकीमती बुलगारी जूलरी सेट को गलत तरीके से अपने पास रखा। जूलरी सेट में शामिल एक नेकलेस, इयररिंग्स, ब्रेसलेट और रिंग्स।

फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का दावा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नियमों का उल्लंघन किया और यह गिफ्ट सस्ते दामों पर अपने पास रख लिया। अगर उन्होंने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। बता दें कि इसी मामले में बुशरा बीबी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

तोशाखाना वह विभाग है, जहां सरकारी अधिकारियों को मिले विदेशी तोहफों को रखा जाता है। इमरान खान के खिलाफ यह आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कई कीमती तोहफों को सस्ते दामों पर खरीदा और निजी उपयोग के लिए रखा। यह मामला इमरान खान के कार्यकाल के दौरान तोशाखाना के दुरुपयोग को लेकर हो रही व्यापक जांच का हिस्सा है। यह मामला न केवल कानूनी मुद्दों को उठाता है, बल्कि इमरान खान के लिए राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इसे लेकर पाकिस्तान की राजनीति में खासी हलचल है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0731-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569